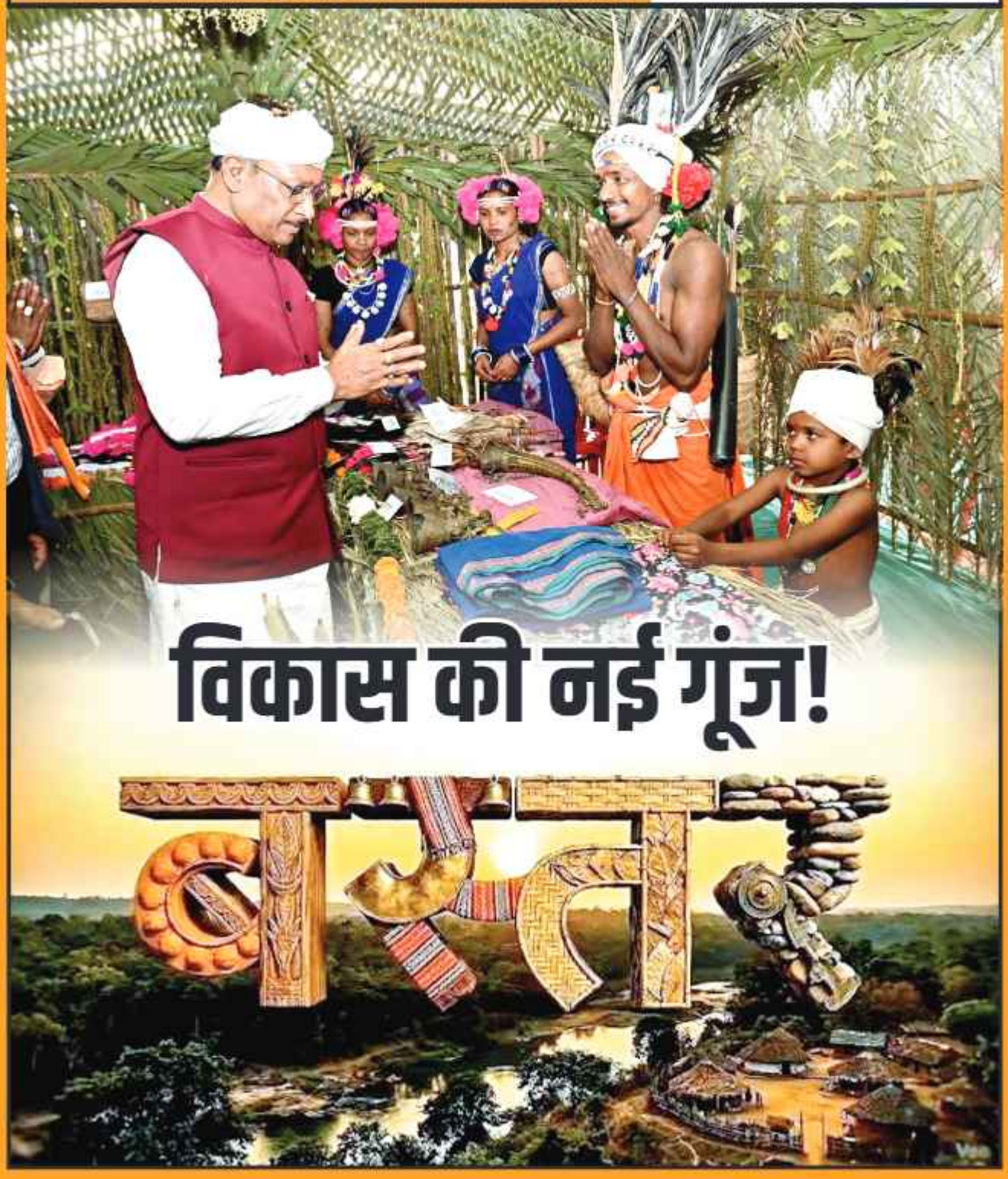
RNI : CTHIN/25/A3260

जनजाति चेतना गौठ

जहां खबर नहीं, असर होता है

• वर्ष : 02 • अंक : 02 • नवंबर 2026 • मूल्य : 25 रुपए



विकास की नई गूंज!


IMP24NEWS
www.imp24news.com

जनता के गोठ

वर्ष : 02
अंक : 02
नवंबर 2026

अंदर के पन्नों पर

www.jantakegoth.com

संपादक
शुभम वर्मा

सलाहकार संपादक
अनिल पुसदकर

ब्यूरो

अविनाश प्रसाद (बस्तर ब्यूरो) 97701 64499
भुजबल बघेल (बकावन, बस्तर) 62662 59437
ओमप्रकाश रजक (बकावंड, बस्तर) 62615 58359
रोहित यादव (बलरामपुर) 79748 30818
चंद्रहास वैष्णव (जगदलपुर) 82238 99000
संजू जैन (धमतरी) 70008 85784
प्रेम दुर्गम (बीजापुर) 63032 84212
भूपेन्द्र सिंह राठौर (बिलासपुर) 75669 08440
जीतु साहू (धमतरी) 84352 18664
लोकेश्वर सिन्हा (गरियाबंद) 79748 44284
तनवीर आलम (गौरेला पेंड्रा मरवाही) 98930 22154
हेमंत पटेल (जांजगीर चांपा) 99265 12822
जितेंद्र सिंह (जशपुर) 94255 69910
उमेश कुमार यादव (कोरबा) 87706 46952
आकाश श्रीवास्तव (कुरुरु, कोरबा जिला) 74706 89880
उग्रसेन पाल (मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर) 96914 42556
त्रिलोक कोशले (मुंगेली) 83599 00249
जाहिद अंसारी (सूरजपुर) 62685 23783
अँचल कुमार वर्मा (उतई /पाटन) 78282 48170
संदीप मिश्रा (दुर्ग) 98934 50338
गोवर्धन लाल सिन्हा (राजनांदगांव) 93037 88975
महबूब खान (कवर्धा) 81092 90209
ओमकार साहू (सिमगा, बलौदाबाजार) 93669 27970

मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव
तरुण बंछोर 83498 38928
हिल्डा कुमार 96856 30335

LAYOUT HITI Graphix 8827988255

कार्यालय

हाउस नंबर 411, देवनगरी, आदिवासी छात्रावास के सामने, शिवशंकर होटल के पीछे, महादेव घाट, रायपुरा, रायपुर (छत्तीसगढ़)

प्रकाशक एवं मुद्रक : शुभम वर्मा द्वारा हाउस नंबर 411, देवनगरी, आदिवासी छात्रावास के सामने, शिवशंकर होटल के पीछे, महादेव घाट, रायपुरा, रायपुर (छत्तीसगढ़) से प्रकाशित एवं दैनिक भास्कर प्रेस, हाउस नंबर 866, वार्ड नंबर 09, अमीन चिप्पर तहसील, रायपुर, रायपुर से मुद्रित।
संपादक-शुभम वर्मा 9300870270, 9425620408, 077143 46242
RNI : CTHIN/26/A3260



10 लाल आतंक के कमजोर पड़ते साये में नई रोशनी



14 रियासतों की शाही विरासत को मिलेगी नई पहचान



36 भव्यता का महाकाव्य

18 सरेंडर से सियासी शक्ति प्रदर्शन तक

21 खेतों में मेहनत, आंखों में आस

24 रंजिश का खौफनाक अंत

30 766 करोड़ के निवेश का खुलेगा राज!

सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन सुरक्षित। प्रकाशित सामग्री के किसी भी प्रकार के उपयोग के पूर्व प्रकाशक संपादक की अनुमति अनिवार्य है। पत्रिका में प्रकाशित रचना, लेखों, विज्ञापनों एवं अन्य प्रकाशित सामग्रियों के विचारों से प्रकाशक संपादक की सहमति से अनिवार्य नहीं है। किसी भी प्रकार के वाद विवाद एवं वैधानिक प्रक्रिया केवल रायपुर न्यायालयीन क्षेत्र के अंतर्गत ही मान्य होगी।

www.jantakegoth.com

जनता के गोठ

जहां खबर नहीं, असर होता है

मासिक पत्रिका





IMP24NEWS

www.imp24news.com

IDEAL Marketing & Production

- Government Documentary Film
- Corporate Film
- Presentation Film
- Live Telecast Setup

संपादकीय

बंदूक के साये से विकास की राह तक बस्तर



बस्तर की तस्वीर बदल रही है। कभी माओवादी हिंसा और भय के कारण जिन गांवों तक पहुंचना मुश्किल था, वहां सड़क, मोबाइल नेटवर्क, सरकारी सेवाएं और विकास की नई संभावनाएं दस्तक दे रही हैं। सुरक्षा बलों की बढ़ती मौजूदगी और कमजोर पड़ते माओवादी प्रभाव ने इस बदलाव के लिए जमीन तैयार की है। लेकिन बस्तर की असली सफलता केवल सुरक्षा के मोर्चे पर मिली बढ़त से तय नहीं होगी, बल्कि इस बात से होगी कि विकास का लाभ अंतिम गांव और अंतिम परिवार तक कितना पहुंचता है। करीब 200 सुरक्षा शिविरों को जनसेवा केंद्रों में बदलने की पहल इसी दिशा में महत्वपूर्ण है। नेटानार का शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा बताता है कि सुरक्षा ढांचे को शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, राशन और सरकारी योजनाओं की पहुंच का माध्यम बनाया जा सकता है। दंतेवाड़ा के लावा गांव में सौर ऊर्जा से चलने वाला सामुदायिक टेलीविजन भी तकनीक के जरिए दूरस्थ बस्तियों को दुनिया से जोड़ने की छोटी, लेकिन सार्थक कोशिश है। फिर भी चुनौतियां कम नहीं हैं। बरसात में कटते रास्ते, पुल-पुलियों का अभाव, कमजोर स्वास्थ्य सुविधाएं, जर्जर छात्रावास और वन्यजीवों के हमले ग्रामीण जीवन को असुरक्षित बनाते हैं। खनन और रेल परियोजनाओं से प्रभावित परिवारों के रोजगार तथा पुनर्वास के सवाल भी जवाब मांगते हैं। बस्तर को केवल सड़क और सुरक्षा शिविरों से नहीं, भरोसे और अवसरों से बदलना होगा। स्थानीय युवाओं को रोजगार, महिलाओं को बाजार, किसानों और वन उपज संग्राहकों को उचित मूल्य तथा आदिवासी समाज को अपनी संस्कृति और अधिकारों की सुरक्षा मिलनी चाहिए। बंदूक का प्रभाव घटना शुरुआत है, मंजिल नहीं। बस्तर का स्थायी बदलाव तभी होगा, जब विकास वहां के लोगों की भागीदारी और आकांक्षाओं से आगे बढ़ेगा।

विकास की नई गूंज!



बस्तर की पहचान लंबे समय तक जंगलों, पहाड़ों और जनजातीय संस्कृति के साथ-साथ माओवादी हिंसा के कारण बनी रही। छत्तीसगढ़ के इस दक्षिणी अंचल के सात जिलों बस्तर, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा के अनेक गांव ऐसे रहे, जहां पहुंचना प्रशासन के लिए चुनौती था। कई इलाकों मे सड़क नही थी, मोबाइल नेटवर्क का नामोनिशान नही था और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए ग्रामीणों को कई किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता था। भय और असुरक्षा के माहौल ने शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और रोजगार की संभावनाओं को भी सीमित कर दिया था। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के विस्तार और माओवादी गतिविधियों मे आई गिरावट के बाद बस्तर के कई इलाकों मे परिस्थितियां बदल रही है। जिन स्थानों पर कभी प्रशासन की नियमित मौजूदगी कठिन थी, वहां अब सड़क निर्माण, मोबाइल टावर, बैंकिंग सुविधा, सरकारी सेवा केंद्र और विकास योजनाओं की पहुंच बढ़ाने के प्रयास दिखाई दे रहे है।



शुभम वर्मा

बदलाव की यह प्रक्रिया केवल भौतिक सुविधाओं तक सीमित नही है। इसका असर लोगों की सोच, बच्चों की आकांक्षाओं, महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और गांवों के भविष्य को लेकर बन रही नई उम्मीदों पर भी पड़ रहा है। बस्तर के सामने अब दोहरी जिम्मेदारी है। एक तरफ सुरक्षा और शांति के माहौल को स्थायी बनाना है, दूसरी तरफ इस अवसर को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सम्मानजनक जीवन की सुविधाओं मे बदलना है। असली विकास तभी होगा, जब बदलाव की यह तस्वीर जगदलपुर या जिला मुख्यालयों तक सीमित न रहकर जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसे अंतिम गांव तक पहुंचे।

मुख्यधारा में कदमताल करता बस्तर का युवा

आज बस्तर में बदलाव की जो बयार बह रही है, वह केवल भौतिक बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित नहीं है; यह बस्तर के जन-मन के सोच में आए सकारात्मक परिवर्तन की परिचायक है। जिस अंचल में कभी बंदूक और हिंसा की गूंज हुआ करती थी, आज वहां की वादियों में किताबों के पन्ने पलटने की सरसराहट और नवाचार की चर्चाएं सुनाई देती हैं। 'सेवा संकल्प अभियान' के जरिए सरकार ने यह सिद्ध कर दिया है कि यदि नीतियां संवेदनशील हों और क्रियान्वयन में प्रतिबद्धता हो, तो सबसे जटिल चुनौतियों को भी अवसरों में बदला जा सकता है। आज बस्तर का युवा न केवल गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा से सशक्त हो रहा है, बल्कि विविध रोजगार, स्वरोजगार और नवाचारों के अवसरों से जुड़कर छत्तीसगढ़ राज्य और संपूर्ण देश की प्रगति में कंधे से कंधा मिलाकर अपनी सशक्त भागीदारी सुनिश्चित कर रहा है। अभावों से उम्मीद और संघर्ष से सफलता की ओर बढ़ता यह बस्तर, नए भारत के निर्माण की एक अनुकरणीय और प्रेरणादायी मिसाल बन चुका है।



सड़क और मोबाइल नेटवर्क ने खोली पहुंच की राह

बस्तर मे विकास की सबसे बड़ी बाधा लंबे समय तक भौगोलिक दुर्गमता और कमजोर संपर्क व्यवस्था रही। कई गांव मुख्य मार्ग से दूर थे। बरसात के दौरान नाले और नदिया रास्ता रोक देते थे। मरीज को अस्पताल ले जाना, बच्चों को स्कूल पहुंचाना या किसान की उपज बाजार तक लाना भी कठिन हो जाता था। सुरक्षा परिस्थितियों मे सुधार के साथ इन इलाकों मे सड़क और संचार नेटवर्क का विस्तार तेज हुआ है। केंद्र सरकार के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार बस्तर संभाग के सात जिलों मे 3,240 किलोमीटर से अधिक सड़कें बनाई गई है और 889 मोबाइल टावर स्थापित किए गए है। इन सुविधाओं से कई गांव बाजार, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, बैंक और सरकारी योजनाओं से जुड़ सके है। यहां एक तथ्यात्मक अंतर समझना जरूरी है। 12,211 किलोमीटर सड़कों और 5,000 मोबाइल टावरों का आंकड़ा देश के माओवादी प्रभावित क्षेत्रों से संबंधित है, केवल बस्तर संभाग का नही। बस्तर के लिए उपलब्ध अलग आंकड़े 3,240 किलोमीटर सड़क और 889 मोबाइल टावर बताते है। सड़क और मोबाइल नेटवर्क का लाभ केवल चला आसान



होने तक सीमित नही है। नेटवर्क पहुंचने से ग्रामीण सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते है, डिजिटल भुगतान कर सकते है और परिवार के सदस्यों से संपर्क बनाए रख सकते है। किसान बाजार भाव और मौसम संबंधी सूचना हासिल कर सकते है। विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन अध्ययन सामग्री और प्रतियोगी परीक्षाओं की जानकारी तक पहुंच आसान हो सकती है। आपात स्थिति मे स्वास्थ्यकर्मी, पुलिस और प्रशासन से संपर्क भी पहले की तुलना मे सहज होता है। हालांकि सड़क निर्माण की सफलता का पैमाना केवल किलोमीटर की संख्या नही हो सकता। यह भी देखना होगा कि कितने गांव सालभर आवागमन के योग्य मार्ग से जुड़े, कितने रास्ते बरसात मे भी खुले रहते है और कितने ग्रामीणों को अस्पताल तथा बाजार तक पहुंचने मे वास्तविक राहत मिली है।

सुरक्षा शिविर से जनसेवा केंद्र तक: बदलती प्रशासनिक भूमिका

बस्तर मे बदलाव की एक उल्लेखनीय पहल सुरक्षा शिविरों को जनसुविधा केंद्र के रूप मे विकसित करने की है। जिन शिविरों की पहचान कभी सुरक्षा बलों की तैनाती से थी, वहां अब ग्रामीणों को सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने की योजना पर काम हो रहा है। इस पहल को शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा नाम दिया गया है। 18 मई 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बस्तर जिले के नेतानार मे पहले शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा जन सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया। योजना के तहत करीब 200 सुरक्षा शिविरों मे से पहले चरण मे 70 शिविरों को सेवा केंद्र के रूप मे विकसित करने की बात कही गई है। इन केंद्रों पर आधार, बैंकिंग, राशन, कौशल प्रशिक्षण और केंद्र तथा राज्य सरकार की योजनाओं से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। नेतानार का चयन भी प्रतीकात्मक महत्व रखता है। यह शहीद वीर गुंडाधुर की जन्मभूमि है। वर्ष 1910 के भूमकाल विद्रोह मे गुंडाधुर ने आदिवासी अस्मिता और अधिकारों के लिए अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ संघर्ष किया था। उसी क्षेत्र मे स्थापित सेवा डेरा इस बात का उदाहरण है कि सुरक्षा व्यवस्था के लिए बने परिसर को स्थानीय जरूरतों के अनुरूप जनसेवा का माध्यम बनाया जा सकता है। इन केंद्रों के जरिए ग्रामीणों को आधार कार्ड बनवाने या अपडेट कराने, बैंक खाते से जुड़ी सेवाएं लेने और विभिन्न प्रमाणपत्रों के लिए आवेदन करने जैसी सुविधाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराने का प्रयास है। बैंक सखी के रूप मे महिलाओं को जोड़ने की पहल से गांव मे ही पैसे निकालने, जमा करने और अन्य बैंकिंग कार्यों की सुविधा बढ़ सकती है। इस मॉडल की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि सेवा डेरों मे नियमित कर्मचारी, जरूरी तकनीकी संसाधन और पर्याप्त इंटरनेट उपलब्ध रहे। केवल भवन या केंद्र खोल देना पर्याप्त नही होगा। ग्रामीणों को हर सेवा के लिए बार-बार जिला मुख्यालय न जाना पड़े, तभी यह पहल अपने उद्देश्य को पूरा कर सकेगी।

लावा गांव की पहली टीवी स्क्रीन, विकास का छोटा लेकिन बड़ा संकेत

बस्तर मे बदलाव की कहानी को समझना हो तो दंतेवाड़ा जिले के कुआकोंडा विकासखंड के लावा गांव का उदाहरण उल्लेखनीय है। बैलाडीला की पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसे इस गांव मे केवल 21 परिवार रहते है। किरंदुल के लौह अयस्क क्षेत्र से करीब आठ किलोमीटर दूर होने के बावजूद गांव तक पक्की सड़क नही है। ग्रामीणों को राशन जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए भी पथरीले रास्तों से पैदल जाना पड़ता है। ऐसे गांव मे छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण और जिला प्रशासन ने सौर ऊर्जा से चलने वाला सामुदायिक टीवी स्थापित किया है। ग्रामीणों ने पहली बार अपने गांव मे टेलीविजन स्क्रीन देखी। यह सुविधा केवल मनोरंजन का साधन नही, बल्कि सूचना और शिक्षा से जुड़ने का नया माध्यम भी है। अब गांव के लोग देश-दुनिया की खबरें, सरकारी योजनाओं की जानकारी, खेती और स्वास्थ्य से जुड़े कार्यक्रम देख सकेंगे। बच्चों को ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों के जरिए सीखने का नया अवसर मिलेगा। लावा की कहानी एक जरूरी सवाल भी सामने रखती है। यदि 21 परिवारों वाले गांव तक पहली बार टीवी पहुंचा है और वहां अब भी पक्की सड़क नही है, तो यह उपलब्धि के साथ विकास की बाकी दूरी का भी संकेत है। सूचना का अधिकार तभी पूरा होगा, जब उसके साथ बिजली, पेयजल, परिवहन, स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाएं भी उपलब्ध हों। सोलर टीवी एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन गांव को सड़क और नियमित सरकारी सेवाओं से जोड़ना अगला जरूरी कदम होना चाहिए।







पर्यटन और जनजातीय संस्कृति से खुलेंगे रोजगार के रास्ते

बस्तर की प्राकृतिक सुंदरता और जनजातीय विरासत उसे देश के प्रमुख पर्यटन क्षेत्रों मे स्थान दिलाने की क्षमता रखती है। चित्रकोट जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात, कांगेर घाटी, अबूझमाड़ और वनांचल के अनेक प्राकृतिक स्थल पर्यटकों को आकर्षित कर सकते है। लंबे समय तक सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण इन स्थलों तक पर्यटन का विस्तार सीमित रहा। अब बेहतर संपर्क और सुरक्षा के माहौल से इस क्षेत्र मे नई संभावनाएं बन रही है। पर्यटन का लाभ तभी स्थानीय लोगों तक पहुंचेगा, जब होमस्टे, स्थानीय गाइड, परिवहन, हस्तशिल्प, खानपान और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों मे ग्रामीणों की भागीदारी हो। केवल पर्यटक स्थल विकसित करने से स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत नही होगी। पर्यटन से होने वाली आय का बड़ा हिस्सा स्थानीय परिवारों तक पहुंचे, इसके लिए प्रशिक्षण, बाजार संपर्क और स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा देना जरूरी है। बस्तर पंडुम और बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजन भी इसी दिशा मे महत्वपूर्ण है। बस्तर पंडुम के जरिए जनजातीय नृत्य, गीत, वेशभूषा, खानपान, आभूषण और हस्तशिल्प को व्यापक मंच मिलता है। वर्ष 2026 के आयोजन मे सात जिलों के 1,885 ग्राम पंचायतों और 32 विकासखंड मुख्यालयों से 55 हजार प्रतिभागियों की भागीदारी की जानकारी दी गई। बस्तर ओलंपिक ने उन युवाओ को खेल के माध्यम से अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर दिया है, जिनकी ऊर्जा और क्षमता लंबे समय तक हिंसा और असुरक्षा के माहौल मे दबकर रह गई थी। वर्ष 2025 के आयोजन मे 3.91 लाख खिलाड़ियों की भागीदारी की जानकारी दी गई। इन आयोजनों का महत्व केवल उत्सव या प्रतियोगिता तक सीमित नही होना चाहिए। स्थानीय कलाकारों को नियमित बाजार, खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और प्रतिभाशाली युवाओ को आगे बढ़ने के अवसर मिलने चाहिए। बस्तर की संस्कृति को पर्यटन का उत्पाद बनाने के बजाय उसके मूल स्वरूप और समुदाय के अधिकारों का सम्मान करते हुए प्रस्तुत करना जरूरी है।



शांति के अवसर को समावेशी विकास मे बदलने की जरूरत

बस्तर की बदलती तस्वीर को केवल सुरक्षा अभियानों या सड़क निर्माण के आंकड़ों से नही मापा जा सकता। यह बदलाव तभी स्थायी होगा, जब गांवों मे रहने वाले लोगों को लगे कि उनके जीवन मे वास्तविक सुधार आया है। बच्चों को बेहतर स्कूल मिले, मरीज को समय पर उपचार मिले, किसान अपनी उपज उचित कीमत पर बेच सके, महिला समूह अपने उत्पादों का बाजार बना सके और युवा को अपने ही क्षेत्र मे सम्मानजनक रोजगार मिले। सुरक्षा बलों की मौजूदगी से तैयार हुआ भरोसा प्रशासन की नियमित मौजूदगी और जनसुविधाओं से मजबूत होना चाहिए। नियद नेल्लानार जैसी योजनाओं का उद्देश्य भी दूरस्थ गांवों तक सड़क, बिजली, पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं पहुंचाना है। इन प्रयासों का मूल्यांकन गांववार और सेवा के आधार पर होना चाहिए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि किस गांव तक कौन-सी सुविधा पहुंची और कहां अब भी कमी है। बस्तर के पास प्राकृतिक संपदा, जनजातीय ज्ञान, कला, संस्कृति और युवा शक्ति का बड़ा आधार है। उसे केवल खनन या पर्यटन के सीमित दायरे मे देखने के बजाय स्थानीय समुदायों की भागीदारी से कृषि, वनोपज, शिक्षा, खेल, हस्तशिल्प और सेवा क्षेत्र का व्यापक विकास करना होगा। कभी जिस बस्तर की चर्चा बंदूक और बारूद के संदर्भ मे होती थी, वहां अब सड़क, स्कूल, मोबाइल नेटवर्क, पर्यटन और रोजगार की बात बढ़ रही है। यह बदलाव एक महत्वपूर्ण अवसर है, लेकिन इसे पूरा होने की कहानी मान लेना जल्दबाजी होगी। लावा जैसे गांव मे पहली बार टीवी पहुंचना जितना उत्साहजनक है, उतना ही जरूरी वहां पक्की सड़क और स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाना भी है। बस्तर की असली विकास गाथा तब लिखी जाएगी, जब जगदलपुर से लेकर अबूझमाड़ और बैलाडीला की पहाड़ियों के बीच बसे हर गांव तक शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और रोजगार की रोशनी पहुंचे। शांति ने रास्ता खोला है, अब उस रास्ते पर समावेशी और टिकाऊ विकास को आगे बढ़ाना ही बस्तर की सबसे बड़ी जरूरत है।

शिक्षा के नए अवसर, लेकिन गुणवत्ता और आवास की चिंता

बस्तर के भविष्य का सबसे बड़ा आधार शिक्षा है। माओवादी हिंसा के कारण कई अंदरूनी इलाकों मे स्कूलों का संचालन प्रभावित हुआ। कुछ गांवों मे स्कूल भवन बंद रहे या बच्चों को पढ़ाई के लिए दूर जाना पड़ा। सुरक्षा परिस्थितियों मे सुधार के बाद ऐसे क्षेत्रों मे शैक्षणिक गतिविधियां फिर शुरू करने के प्रयास हुए है। बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर जिलों मे लंबे समय से बंद रहे 298 स्कूलों के फिर से खुलने की जानकारी भी सामने आई है। शिक्षा के क्षेत्र मे पोर्टा केबिन, आवासीय स्कूल, शिक्षा नगर और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से जुड़े कार्यक्रमों ने आदिवासी विद्यार्थियों के लिए अवसर बढ़ाए है। कांकेर जिले मे मावा मोदोल पहल के तहत चयनित विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की नि:शुल्क कोचिंग, डिजिटल कक्षाएं और पुस्तकालय जैसी सुविधाएं दी जा रही है। लेकिन स्कूल खुलना और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलना अलग-अलग बातें है। अंदरूनी गांवों मे शिक्षकों की नियमित उपस्थिति, विषय विशेषज्ञों की उपलब्धता, विज्ञान और गणित की पढ़ाई, डिजिटल संसाधन तथा बच्चों की भाषा से जुड़ी जरूरतों पर ध्यान देना होगा। आदिवासी बच्चों के लिए मातृभाषा और स्थानीय बोली को शुरुआती शिक्षा से जोड़ना भी जरूरी है। छात्रावासों की स्थिति भी गंभीरता से देखने की जरूरत है। कई परिवारों के बच्चे पढ़ाई के लिए घर से दूर आवासीय संस्थानों मे रहते है। ऐसे मे जर्जर भवन, स्वच्छ पेयजल, शौचालय, भोजन, सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी सीधे उनकी पढ़ाई और जीवन को प्रभावित करती है। छात्रावास केवल रहने की जगह नही, बल्कि बच्चों के सुरक्षित भविष्य का आधार है। इसलिए इनके रखरखाव और नियमित निरीक्षण को प्राथमिकता देनी होगी।





वनोपज, कृषि व महिला समूहों से स्थानीय अर्थव्यवस्था को आधार

बस्तर की आर्थिक ताकत केवल खनिज संपदा मे नही, बल्कि जंगल और कृषि आधारित आजीविका मे भी है। महुआ, इमली, चिरौंजी, साल बीज और अन्य वनोपज हजारों परिवारों की आय का आधार है। इन उत्पादों का स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण और बेहतर पैकेजिंग हो तो ग्रामीणों को कच्चा माल बेचने की मजबूरी से राहत मिल सकती है। नेतानार मे महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा इमली का प्रसंस्करण कर पल्प तैयार करने का काम इसी संभावना को दिखाता है। पारंपरिक ढेंकी से चावल तैयार करना, उसकी बिक्री और सिलाई प्रशिक्षण जैसी गतिविधियां भी महिलाओं को आय के नए साधन दे सकती है। उत्पादों की गुणवत्ता, पैकेजिंग और ब्रांडिंग सुधारने के लिए डिजाइन संस्थानों की मदद लेने की पहल से स्थानीय उत्पादों को बड़े बाजार तक पहुंचाने का अवसर बन सकता है। पशुपालन और डेयरी क्षेत्र मे भी संभावनाएं है। ग्रामीण महिलाओं को पशुपालन से जोड़ने, दूध संग्रह केंद्र बनाने और सहकारी नेटवर्क विकसित करने से नियमित आय का आधार तैयार हो सकता है। लेकिन इसके लिए पशु चिकित्सा सेवा, चारा, प्रशिक्षण, शीत श्रृंखला और दूध के खरीदारों की व्यवस्था जरूरी है। वनोपज के कारोबार मे भी संग्रहकर्ता को उचित मूल्य, पारदर्शी तौल और समय पर भुगतान मिलना चाहिए।

विकास की राह मे अब भी खड़ी है बुनियादी सुविधाओं की चुनौती

बस्तर मे बदलाव के संकेत स्पष्ट है, लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बीजापुर के बासागुड़ा क्षेत्र के आसपास कई गांवों मे नदी पार करने के लिए ग्रामीणों को अब भी अस्थायी पुलों और स्थानीय साधनों पर निर्भर रहना पड़ता है। कोंडागांव के चनिया-फरसगांव जैसे क्षेत्रों मे भी पुलिया और सड़क की मांग उठती रही है। बरसात मे गांवों का संपर्क टूटने से बच्चों की पढ़ाई, मरीजों का उपचार और राशन की आपूर्ति प्रभावित होती है। स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच भी बड़ी चुनौती है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों मे डॉक्टर, नर्स, दवाइयां, जांच सुविधा और एंबुलेंस की उपलब्धता नियमित होनी चाहिए। दूरस्थ गांवों मे स्वास्थ्यकर्मी पहुंचने के लिए सड़क और परिवहन जरूरी है। बस्तर संभाग मे स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए बड़े स्तर पर जांच अभियान चलाए गए है, लेकिन जांच के बाद उपचार, दवा और नियमित निगरानी की व्यवस्था भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। वन्यजीवों के साथ सह-अस्तित्व भी ग्रामीण जीवन का महत्वपूर्ण सवाल है। भालू, तेंदुआ और बाघ जैसे वन्यजीवों की आवाजाही वाले क्षेत्रों मे लोगों की सुरक्षा, समय पर सूचना, मुआवजा और वन विभाग की त्वरित सहायता की व्यवस्था मजबूत करनी होगी। जंगल के साथ जीवन बिताने वाले समुदायों को सुरक्षित आजीविका उपलब्ध कराना भी जरूरी है। खनन क्षेत्रों मे स्थानीय युवाओं को रोजगार और रावघाट रेल परियोजना से प्रभावित परिवारों की अपेक्षाओं को पूरा करना भी विकास की विश्वसनीयता से जुड़ा है। जिन परिवारों ने परियोजनाओं के लिए जमीन दी है, उन्हें रोजगार, पुनर्वास और मुआवजे से जुड़े वादों का लाभ समय पर मिलना चाहिए। खनिज संपदा से होने वाली आर्थिक गतिविधियों मे स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित किए बिना समावेशी विकास का लक्ष्य अधूरा रहेगा।

लाल आतंक के कमजोर पड़ते साये में नई रोशनी

जवानों के साथ दीपावली मनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया बस्तर को बड़ा संदेश

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के बस्तर दशहरा में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री का दौरा महज संयोग नहीं, बदलते बस्तर की राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्यता का संकेत। सुरक्षा अभियान की सफलता के साथ अब विकास, भरोसे और स्थायी शांति की चुनौती भी अहम। बस्तर की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सुरक्षा बलों के जवानों के साथ दीपावली मनाना सामान्य राजनीतिक दौरा नहीं है। दशकों तक नक्सली हिंसा, बारूदी सुरंगों और भय के साये में रहे इस अंचल में देश के प्रधानमंत्री का पहुंचना अपने आप में एक बड़ा संदेश है। यह संदेश उन जवानों के सम्मान का है, जिन्होंने दुर्गम जंगलों में कठिन परिस्थितियों के बीच मोर्चा संभाला। साथ ही यह उस बदलाव को राष्ट्रीय मंच पर रेखांकित करने का प्रयास भी है, जिसके तहत बस्तर की पहचान हिंसा से हटकर शांति, कनेक्टिविटी और विकास की ओर बढ़ रही है। इस दौरे का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि महज दो सप्ताह के अंतराल में देश की दो सर्वोच्च राजनीतिक हस्तियां बस्तर पहुंची हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु 25 अक्टूबर को जगदलपुर में बस्तर दशहरा के आयोजन में शामिल हुई थीं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपावली का पर्व जवानों के बीच मनाने के लिए इसी अंचल को चुना। इन दोनों दौरों को अलग-अलग कार्यक्रम मानकर नहीं देखा जा सकता। इनके पीछे बस्तर को लेकर बदलती राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और इस क्षेत्र को देश की मुख्यधारा से जोड़ने के संकल्प का संकेत दिखाई देता है।



बारूद की जगह विकास की पहचान बनाने की कोशिश

बस्तर की पहचान लंबे समय तक नक्सली हिंसा और सुरक्षा चुनौतियों से जुड़ी रही। सड़क निर्माण से लेकर स्कूल खोलने और स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने तक, हर काम के सामने सुरक्षा का सवाल खड़ा रहता था। कई इलाकों में सरकारी योजनाओं की पहुंच सीमित थी। विकास कार्यों में बाधा डालना और स्थानीय लोगों को भय के वातावरण में रखना नक्सली रणनीति का हिस्सा रहा। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षा बलों के लगातार अभियानों, नए सुरक्षा शिविरों और प्रशासन की पहुंच बढ़ने से परिस्थितियों में बदलाव आया है। जिन क्षेत्रों में कभी सरकारी अमले का पहुंचना मुश्किल था, वहां सड़क, संचार और दूसरी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। स्कूल, अस्पताल और सरकारी सेवाएं पहुंचाने की कोशिशें तेज हुई हैं। इस बदलाव में सुरक्षा बलों की भूमिका निर्णायक रही है। प्रधानमंत्री का बस्तर पहुंचना इसी परिवर्तन को सामने रखने का अवसर है। उनका संदेश साफ है कि जिस क्षेत्र को कभी हिंसा के कारण अलग-थलग माना जाता था, वह अब विकास की नई संभावनाओं के साथ आगे बढ़ सकता है। हालांकि, यह भी समझना जरूरी है कि नक्सली प्रभाव का कमजोर होना और स्थायी शांति स्थापित होना दो अलग-अलग स्थितियां हैं। सुरक्षा बलों के तलाशी अभियान जारी हैं। जंगलों में हथियारों, विस्फोटकों और सुरंग बमों की तलाश तथा उन्हें निष्क्रिय करने का काम अभी बाकी है। इसलिए इस बदलाव को महत्वपूर्ण उपलब्धि मानते हुए भी चुनौती के पूरी तरह समाप्त होने का दावा करना जल्दबाजी होगी।

जवानों के बीच दीपावली, सम्मान से आगे भरोसे का संदेश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस्तर की ओर रवाना होते हुए अपने संदेश में कहा कि वह उन वीर सुरक्षा कर्मियों के साथ दीपावली मनाने जा रहे हैं, जहां कभी नक्सलवाद का प्रभाव था और अब विकास फल-फूल रहा है। उन्होंने जवानों के बलिदान, निस्वार्थ सेवा और राष्ट्र के प्रति समर्पण को नमन करने की बात कही। प्रधानमंत्री के लिए जवानों के साथ दीपावली मनाना नया नहीं है। वह पहले भी अलग-अलग मोर्चों पर तैनात सैनिकों और सुरक्षा कर्मियों के बीच पहुंचकर पर्व मनाते रहे हैं। लेकिन इस बार बस्तर का चयन विशेष महत्व रखता है। यहां तैनात जवान केवल एक सुरक्षा अभियान का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि वे ऐसे क्षेत्र में सामान्य जीवन की वापसी का रास्ता भी तैयार कर रहे हैं, जहां हिंसा ने पीढ़ियों तक लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। जवानों के बीच प्रधानमंत्री की मौजूदगी उनके मनोबल को मजबूती देने के साथ यह भरोसा भी देती है कि उनके कठिन दायित्व और बलिदान को देश का नेतृत्व समझता है। दुर्गम जंगलों में तैनाती, लगातार खतरे के बीच अभियान और स्थानीय परिस्थितियों की कठिनाइयां उनके काम को बेहद चुनौतीपूर्ण बनाती हैं। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री का उनके साथ त्योहार मनाना प्रतीकात्मक होने के साथ भावनात्मक महत्व भी रखता है।



राष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय प्राथमिकता का संकेत

बस्तर दशहरा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु की उपस्थिति का अपना सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व था। बस्तर दशहरा केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आदिवासी परंपरा, लोक आस्था और सामुदायिक जीवन का विशिष्ट प्रतीक है। राष्ट्रपति की मौजूदगी ने इस परंपरा को राष्ट्रीय पहचान देने का काम किया। अब प्रधानमंत्री का दीपावली पर बस्तर पहुंचना सुरक्षा और विकास के सवाल को केंद्र में ला रहा है। दोनों दौरों का संदेश अलग-अलग होते हुए भी एक-दूसरे से जुड़ता है। राष्ट्रपति की यात्रा ने बस्तर की सांस्कृतिक विरासत और आदिवासी अस्मिता को रेखांकित किया, जबकि प्रधानमंत्री का दौरा सुरक्षा बलों के योगदान और बदलती परिस्थितियों को सामने रखता है। इससे यह संकेत मिलता है कि बस्तर को केवल नक्सलवाद की समस्या के रूप में नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति, संसाधनों और विकास की संभावनाओं वाले क्षेत्र के रूप में देखा जाना चाहिए।

बंदूक के साये से बाहर निकलने की असली परीक्षा

बस्तर में सुरक्षा बलों की उपलब्धियों के साथ सबसे बड़ी जरूरत यह सुनिश्चित करना है कि शांति का लाभ स्थानीय लोगों तक पहुंचे। सड़क और मोबाइल नेटवर्क का विस्तार तभी सार्थक होगा, जब उसके साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आजीविका के अवसर भी बढ़ें। आदिवासी युवाओं को स्थानीय स्तर पर काम मिले, किसानों और वन उत्पाद संग्राहकों को अपनी उपज का उचित मूल्य मिले तथा दुरस्थ गांवों तक सरकारी योजनाओं की पहुंच बने। नक्सलवाद के प्रभाव में रहे इलाकों में केवल सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करना पर्याप्त नहीं है। वहां प्रशासन के प्रति विश्वास पैदा करना भी जरूरी है। लोगों को यह महसूस होना चाहिए कि सरकार की मौजूदगी केवल सुरक्षा अभियान तक सीमित नहीं, बल्कि उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी है। विकास की प्रक्रिया में स्थानीय संस्कृति, परंपरा और आदिवासी अधिकारों का सम्मान बना रहना चाहिए। यही वह आधार होगा, जिस पर स्थायी शांति खड़ी हो सकती है।

सरकार की सक्रियता और प्रतिबद्धता का संदेश

प्रधानमंत्री का यह दौरा छत्तीसगढ़ की राजनीति के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। राज्य में भाजपा सरकार नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई और बस्तर में विकास को अपनी प्रमुख उपलब्धियों के रूप में प्रस्तुत करती रही है। ऐसे समय में प्रधानमंत्री का स्वयं जवानों के बीच पहुंचना केंद्र और राज्य सरकार की साझा रणनीति को राजनीतिक समर्थन देता है। इससे आदिवासी अंचल में सरकार की सक्रियता और प्रतिबद्धता का संदेश भी जाता है। लेकिन बस्तर में राजनीतिक भरोसा केवल बड़े आयोजनों और दौरों से नहीं बनेगा। स्थानीय लोगों के जीवन में बदलाव, युवाओं को रोजगार, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं ही सरकार की स्थायी स्वीकार्यता तय करेंगी। नक्सलवाद के खिलाफ अभियान की सफलता का अंतिम पैमाना यह नहीं होगा कि कितने इलाके सुरक्षा बलों की पहुंच में आए, बल्कि यह होगा कि वहां के लोग बिना भय के अपने जीवन, आजीविका और भविष्य के फैसले ले सकें। बस्तर में जवानों के साथ दीपावली मनाकर प्रधानमंत्री ने अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ते एक क्षेत्र की तस्वीर देश के सामने रखी है। यह उन जवानों के सम्मान का अवसर है, जिनके त्याग से बदलाव की जमीन तैयार हुई। लेकिन इस रोशनी को स्थायी बनाने की जिम्मेदारी अब सुरक्षा के साथ विकास, संवेदनशील प्रशासन और स्थानीय जनता के भरोसे पर भी है। बस्तर की असली जीत उस दिन होगी, जब यहां दीपावली का उजाला किसी विशेष दौरे या सुरक्षा अभियान का प्रतीक न रहकर हर गांव के सामान्य जीवन का हिस्सा बन जाएगा।

संघर्ष, संकल्प और विकास का स्वर्णिम सफर

छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के छब्बीस बरस पूरे

एक नवंबर 2000 को मध्यप्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य बना था। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के दूरदर्शी नेतृत्व में यह सपना साकार हुआ था। 1 नवंबर 2000 को जब मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ एक नए राज्य के रूप में मानचित्र पर आया था, तब संसाधनों की कमी, प्रशासनिक चुनौतियों और पिछड़ेपन के बीच एक भविष्य गढ़ने की चुनौती सामने थी। आज अपनी स्थापना के 26 गौरवशाली वर्ष पूरे करते हुए छत्तीसगढ़ ने विकास के क्षेत्र में जो मील के पत्थर स्थापित किए हैं, वे न केवल प्रेरणादायक हैं, बल्कि यह दर्शाते हैं कि दृढ़ इच्छाशक्ति और जनसहभागिता से किसी भी राज्य की तकदीर कैसे बदली जा सकती है। छत्तीसगढ़ अपने संसाधनों को आर्थिक अवसरों में बदलने की क्षमता रखता है। राज्य का लक्ष्य किसानों को समृद्ध करना, महिलाओं को सशक्त बनाना और युवाओं को अवसर देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का संकल्प ले रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार छत्तीसगढ़ अजोर विजन 2047 के तहत विकसित और आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए अग्रसर है। बस्तर के जंगलों में मौजूद सुरक्षा कैंप अब दूरदराज के गांव वालों के लिए सेवा और विकास के केंद्र बन रहे हैं। दूरस्थ गांवों में सार्वजनिक परिवहन के लिए 'मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा' शुरू की गई है। बस्तर में सड़क, पुल, मोबाइल नेटवर्क, उचित मूल्य दुकान, स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल और आंगनबाड़ी जैसी सुविधाओं का विस्तार हो रहा है।

बजट और अर्थव्यवस्था में ऐतिहासिक छलांग

राज्य के गठन के शुरुआती दौर में सीमित वित्तीय संसाधनों के साथ करीब 7,000-8,000 करोड़ रुपये से शुरू हुआ छत्तीसगढ़ का बजट आज बढ़कर 1.72 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है। यह इस बात का प्रमाण है कि राज्य की आर्थिकी तेजी से मजबूत हुई है। देश के 'धान के कटोरे' के रूप में पहचाना जाने वाला यह प्रदेश आज अपनी खनिज संपदा (कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट), इस्पात, सीमेंट और ऊर्जा उत्पादन के बूते देश के औद्योगिक नक्शे पर एक मजबूत स्तंभ बन चुका है। वैश्विक निवेश और आधुनिक उद्योगों के विस्तार से राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है।

महिला सशक्तिकरण



महिला सशक्तिकरण साय सरकार की प्रमुख पहचान के रूप में उभरा है। महतारी वंदन योजना की 31 किस्तों में लगभग 68 लाख पात्र महिलाओं को 20 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे खातों में दी जा चुकी है। प्रदेश में 13.85 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। बिहान मिशन में प्रदेश के 31 लाख से अधिक गरीब परिवारों की महिलाएं स्व-सहायता समूहों से जुड़ी हैं। महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के लिए संपत्ति की रजिस्ट्री में पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत और स्टाम्प शुल्क में एक प्रतिशत की रियायत दी गई है।

आधारभूत संरचना और संपर्क का विस्तार

बीते ढाई दशकों में छत्तीसगढ़ के बुनियादी ढांचे में अभूतपूर्व बदलाव आया है। गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने (ग्रामीण सड़क नेटवर्क में लगभग 98 गुना वृद्धि) से लेकर राजधानी रायपुर और नवा रायपुर (अटल नगर) जैसी आधुनिक शहरी बसाहट ने राज्य के स्वरूप को पूरी तरह बदल दिया है। दूर-दराज के आदिवासी और वन अंचलों तक बिजली, पानी, पक्की सड़कें और डिजिटल कनेक्टिविटी (मोबाइल व इंटरनेट) पहुंच चुकी है, जिससे गांवों और शहरों के बीच की दूरियां सिमटी हैं। नवा रायपुर में डाटा सेंटर और आधुनिक तकनीक परियोजनाएं नई अर्थव्यवस्था से जुड़ रही हैं। सरकार सुशासन, वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत कर रही है। छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास का केंद्र रोजगार सृजन और युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार है। प्रदेश की प्राकृतिक संपदा, कृषि उत्पादन और बेहतर अधोसंरचना निवेश के लिए अनुकूल आधार प्रदान करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, टेक्सटाइल और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ ने 450 से अधिक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार लागू किए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक्ट 2026 लाने वाला राज्य देश का पहला राज्य बना। जन विश्वास सुधारों के जरिए 279 छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया। वन-क्लिक सिंगल विंडो व्यवस्था, सरल भूमि डायवर्जन और रजिस्ट्री के बाद स्वतः नामांतरण जैसे सुधार किए गए हैं। नई औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के बाद 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिनसे 1.72लाख से अधिक संभावित रोजगार के अवसर निर्मित होंगे।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ताकत हमारे किसान

प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण) में अब तक 24.40 लाख आवास स्वीकृत हो चुके हैं। प्रदेश में औसतन करीब 1,600 आवास प्रतिदिन पूरे किए जा रहे हैं। ढाई वर्षों में पुराने और नए स्वीकृत आवास मिलाकर 11 लाख से अधिक घर लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान बेचने की सुविधा दी गई। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में 25.24 लाख किसानों से 141.04 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया। समर्थन मूल्य और कृषक उन्नति योजना को मिलाकर किसानों को लगभग 43,723 करोड़ रुपए की राशि दी गई। खरीदी व्यवस्था में ऑनलाइन टोकन, बायोमेट्रिक सत्यापन और रियल टाइम मॉनिटरिंग जैसे सुधार किसानों के लिए काफी सुविधाजनक रहे। बस्तर संभाग के दुरस्थ, दुर्गम और जनजातीय क्षेत्रों में सड़क संपर्क के विस्तार की दिशा में केंद्र सरकार से महत्वपूर्ण उपलब्धि मिली है। बस्तर की 485 बसाहटों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए स्वीकृति मिल चुकी है, वहीं 280 अन्य बसाहटों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने के लिए 804.06 करोड़ रुपए की लागत के 263 सड़क कार्यों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। बस्तर में नक्सलवाद के विरुद्ध निर्णायक अभियान के साथ विकास की गति को तेज करने तथा दुरस्थ गांवों को मुख्यधारा से जोड़ने के राज्य सरकार के प्रयासों को केंद्र सरकार का सहयोग मिल रहा है।

शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास

मानव संसाधन विकास के बिना किसी भी राज्य की तरक्की अधूरी है। पिछले 26 वर्षों में इस दिशा में भी क्रांतिकारी कार्य हुए हैं। राज्य में साक्षरता दर बढ़कर करीब 79 प्रतिशत तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य सुविधाओं का दायरा बढ़ाते हुए जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों की संख्या में कई गुना इजाफा हुआ है, जिससे आम जनता को घर के नजदीक बेहतर इलाज मिलने लगा है। इसके अलावा, 'बिहान' योजना जैसी पहलों के माध्यम से राज्य की लाखों महिलाओं (स्व-सहायता समूहों) को आजीविका और आर्थिक स्वावलंबन से जोड़कर समाज की मुख्यधारा में मजबूती से स्थापित किया गया है।

मेडिकल कॉलेजों की संख्या में इजाफा

राजधानी रायपुर के नवा रायपुर क्षेत्र में मेडिसिटी हब विकसित किया जा रहा है, जिसमें 5,000 बिस्तरों वाला सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल स्थापित करने की योजना है। रायपुर के डॉ. भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय (मेकाहारा) में 700 बिस्तरों का अस्पताल तथा प्रदेश में 4 नए मेडिकल कॉलेजों का विस्तार किया जा रहा है। राज्य में शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना, श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना, दाई दीदी मोबाइल क्लीनिक योजना, और बच्चों के लिए राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (चिरायु) जैसी योजनाएं संचालित हो रही हैं।

स्वस्थ छत्तीसगढ़ की परिकल्पना हो रहा साकार

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि चिकित्सा सेवाओं के विस्तार को गति प्रदान करते हुए गुणवत्तापूर्ण उपचार की उपलब्धता दुरस्थ क्षेत्रों तक सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण एवं सेवाओं की पहुंच में सुधार के माध्यम से "स्वस्थ छत्तीसगढ़" की परिकल्पना को साकार किया जा रहा है, जो "विकसित छत्तीसगढ़" के लक्ष्य की प्राप्ति का आधार बनेगा। आज प्रदेश में आईआईएम, आईआईटी, ट्रिपल आईटी, एनआईटी, एम्स, लॉ यूनिवर्सिटी जैसी कई बड़ी संस्थाएं खुल गई हैं. इसके अलावा स्कूली शिक्षा में भी काफी विकास हुआ है हालांकि अभी इस दिशा में और काम करने की आवश्यकता है

सुरक्षा, शांति और बस्तर की नई सुबह

छत्तीसगढ़ के विकास मार्ग में सबसे बड़ी बाधा रहे नक्सलवाद के खिलाफ पिछले कुछ वर्षों में निर्णायक और प्रभावी कदम उठाए गए हैं। सुरक्षा बलों के साहस, दुरदराज के क्षेत्रों में नए सुरक्षा शिविरों की स्थापना और साथ ही वहां शिक्षा, स्वास्थ्य व विकास योजनाओं के पहुंचने से लाल आतंक का दायरा तेजी से सिमटा है। बस्तर और सरगुजा के संवेदनहीन समझे जाने वाले कई इलाकों में अब विकास की किरणें पहुंच रही हैं, जिससे वहां के नागरिकों के जीवन में एक नया सवेरा और सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित हो रहा है।

जनता की संतुष्टि और वास्तविक समाधान ही पैमाना

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 का मूल मंत्र होना चाहिए संवेदनशीलता, समयबद्धता और समाधान। अंतिम लक्ष्य यही है कि नागरिक को यह भरोसा हो कि उसने सरकार तक अपनी बात पहुंचाई है, तो उसकी बात सुनी भी जाएगी और नियमानुसार उसका समाधान भी होगा। शासकीय कार्यालय में आने वाले नागरिक के साथ सम्मान और संवेदनशीलता से व्यवहार हो। उसकी बात सुनी जाए और समयबद्ध जवाब दिया जाए। काम नियमानुसार संभव है तो अनावश्यक विलंब न हो। यदि काम संभव नहीं है तो नागरिक को स्पष्ट कारण बताया जाए। लोगों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने की स्थिति न्यूनतम होनी चाहिए। जनता से अच्छा व्यवहार भी अधिकारी-कर्मचारी के प्रदर्शन का महत्वपूर्ण पैमाना होना चाहिए। 26 वर्षों की यह युवा यात्रा इस बात का गवाह है कि छत्तीसगढ़ ने तमाम भौगोलिक और सामाजिक चुनौतियों को पार करते हुए प्रगति के नए आयाम रचे हैं। हालांकि, इस सफर में अभी किसानों की समृद्धि, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसरों के विस्तार और अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं के शत-प्रतिशत लाभ को पहुंचाने की दिशा में निरंतर काम जारी है। 'विकसित छत्तीसगढ़के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा यह राज्य आने वाले समय में देश के सबसे विकसित और सशक्त राज्यों में अपनी एक अलग मिसाल पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

रियासतों की शाही विरासत को मिलेगी नई पहचान

राजदरबारों से लेकर राजवंशों की वंशावलियों तक सहेजा जाएगा छत्तीसगढ़ का गौरवशाली अतीत



छत्तीसगढ़ के पुराने महलों को हेरिटेज पर्यटन और होमस्टे से जोड़ने की भी तैयारी

छत्तीसगढ़ का इतिहास केवल आदिवासी संस्कृति, प्राचीन मंदिरों और प्राकृतिक संपदा तक सीमित नहीं है। इसकी ऐतिहासिक पहचान में उन 14 रियासतों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिनके अपने राजवंश, शासन तंत्र, दरबार, परंपराएं और सांस्कृतिक विशेषताएं थीं। इन रियासतों के महलों में कभी राजकीय फैसले लिए जाते थे, शाही मुहरों से आदेश जारी होते थे और स्थानीय प्रशासन का संचालन राजपरिवारों के माध्यम से होता था। समय के साथ इन रियासतों की राजनीतिक सत्ता भले ही समाप्त हो गई, लेकिन उनकी ऐतिहासिक विरासत आज भी महलों, पुराने दस्तावेजों, पारिवारिक अभिलेखों और लोक परंपराओं में मौजूद है। अब इस बिखरी हुई विरासत को एक स्थान पर सजोने की तैयारी है। राज्य सरकार राजधानी रायपुर स्थित संस्कृति विभाग में दो मंजिला 'रियासत वीथिका' विकसित करने जा रही है। इसका उद्देश्य प्रदेश की 14 ऐतिहासिक रियासतों के इतिहास, राजपरिवारों की वंशावलियों, शाही परंपराओं और दुर्लभ वस्तुओं को व्यवस्थित रूप से संरक्षित करना है। यह पहल केवल एक संग्रहालय बनाने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि छत्तीसगढ़ के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास को नई पीढ़ी के सामने प्रस्तुत करने का माध्यम भी बनेगी।

महलों और निजी संग्रहों से बाहर आएगा इतिहास

प्रदेश की कई रियासतों से जुड़ी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक वस्तुएं आज भी राजपरिवारों के निजी महलों, पारिवारिक संग्रहों और क्षेत्रीय संग्रहालयों में सुरक्षित हैं। इनमें शाही मुहरें, पुराने सिक्के, पारंपरिक वस्त्र, हथियार, राजदरबार में उपयोग होने वाली सामग्री और शासनकाल के महत्वपूर्ण दस्तावेज शामिल हैं। इनमें से अधिकांश धरोहरों के बारे में आम लोगों को बहुत कम जानकारी है। प्रस्तावित वीथिका में इन वस्तुओं को प्रदर्शित करने के साथ प्रत्येक रियासत की स्थापना, राजवंश, शासन व्यवस्था और सांस्कृतिक योगदान का विवरण भी उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए पर्यटन एवं संस्कृति विभाग ने परियोजना का प्रारूप तैयार कर लिया है। पूर्व राजपरिवारों के वंशजों और प्रतिनिधियों के साथ परामर्श बैठक कर योजना का प्रस्तुतिकरण भी किया गया है। विभाग एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने की तैयारी में है, जो अलग-अलग राजपरिवारों से संपर्क कर उनके पास उपलब्ध ऐतिहासिक सामग्री जुटाएगा। साथ ही मौखिक इतिहास का संकलन, पुरानी वंशावलियों का सत्यापन और अभिलेखों का दस्तावेजीकरण भी किया जाएगा। इससे उन ऐतिहासिक तथ्यों को सामने लाने में मदद मिलेगी, जो अब तक पारिवारिक स्मृतियों और निजी दस्तावेजों तक सीमित रहे हैं।

राजमहलों को पर्यटन की नई अर्थव्यवस्था से जोड़ने की तैयारी

सरकार की योजना रियासतों का इतिहास प्रदर्शित करने के साथ उनके ऐतिहासिक महलों को भी पर्यटन के नक्शे पर प्रमुखता से स्थापित करने की है। इसके लिए हेरिटेज टूरिज्म सर्किट और होमस्टे विकसित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। यदि पुराने राजमहलों को संरक्षित कर पर्यटकों के लिए व्यवस्थित रूप से खोला जाता है तो छत्तीसगढ़ में पर्यटन का एक नया आकर्षण विकसित हो सकता है। पर्यटक केवल ऐतिहासिक इमारतों को देखने तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि राजपरिवारों की जीवनशैली, खानपान, पारंपरिक कलाओं और स्थानीय सांस्कृतिक विरासत को भी करीब से जान सकेंगे। इससे संबंधित क्षेत्रों में स्थानीय गाइड, हस्तशिल्प, पारंपरिक खानपान, परिवहन और होमस्टे जैसी गतिविधियों

के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। खासकर छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को इसका लाभ मिल सकता है। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष नीलू शर्मा का मानना है कि प्रदेश की रियासतों ने यहां की सांस्कृतिक, पुरातात्विक और धार्मिक पहचान को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन धरोहरों को पर्यटन से जोड़ने पर छत्तीसगढ़ का इतिहास देशभर के लोगों तक पहुंच सकेगा।

इतिहास संरक्षण के साथ प्रामाणिकता भी जरूरी

रियासत वीथिका की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इसमें प्रदर्शित होने वाली सामग्री कितनी प्रामाणिक, प्रमाणित और शोधपरक होती है। राजपरिवारों की वंशावलियों, पुराने दस्तावेजों और मौखिक इतिहास का ऐतिहासिक अभिलेखों से मिलान करना आवश्यक होगा। साथ ही अलग-अलग रियासतों के शासनकाल में आम जनता, किसानों, आदिवासी समाज और स्थानीय संस्थाओं की भूमिका को भी पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए। इतिहास को केवल राजाओं और महलों की कहानी तक सीमित रखना इसकी व्यापकता को कम कर देगा। संस्कृति विभाग के सचिव डॉ. एस. भारतीदासन के अनुसार, गैलरी में राजदरबार की व्यवस्था, शाही मुहरों, सिक्कों, हथियारों, पोशाकों और सामाजिक-सांस्कृतिक परंपराओं का दस्तावेजीकरण किया जाएगा। वहीं संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के संचालक डॉ. संजय कन्नौजे के मुताबिक, दो मंजिला गैलरी के माध्यम से पर्यटकों को प्रदेश की सभी रियासतों का इतिहास एक ही स्थान पर जानने का अवसर मिलेगा।

अतीत को सहेजने से बनेगी भविष्य की नई पहचान

छत्तीसगढ़ की 14 रियासतें केवल राजाओं और राजमहलों का इतिहास नहीं हैं। इनके भीतर शासन व्यवस्था के विकास, सामाजिक बदलाव, कला संरक्षण, धार्मिक परंपराओं और क्षेत्रीय संस्कृति की अनेक कहानियां छिपी हैं। रियासत वीथिका के माध्यम से इन कहानियों को एक व्यवस्थित मंच मिल सकता है। अब तक अलग-अलग स्थानों पर बिखरी ऐतिहासिक धरोहरों को एक जगह लाने की यह पहल प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण हो सकती है। जरूरत इस बात की है कि संग्रहालय के साथ ऐतिहासिक महलों का संरक्षण, अभिलेखों का डिजिटलीकरण और पर्यटन सुविधाओं का विकास भी समानांतर रूप से किया जाए। दरअसल, किसी प्रदेश की पहचान केवल उसके वर्तमान विकास से नहीं, बल्कि अपनी विरासत को सहेजने की क्षमता से भी बनती है। छत्तीसगढ़ की रियासत वीथिका यदि इतिहास, शोध, संस्कृति और पर्यटन को एक सूत्र में जोड़ पाती है तो यह आने वाली पीढ़ियों के लिए अतीत से संवाद करने का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन सकती है।



हर रियासत की है अपनी अलग पहचान

छत्तीसगढ़ की 14 रियासतों का इतिहास एक जैसा नहीं रहा। कहीं राजवंशों की प्राचीन परंपराएं हैं तो कहीं कला, संगीत, स्थापत्य और जनजातीय संस्कृति के संरक्षण की उल्लेखनीय विरासत दिखाई देती है।

बस्तर

बस्तर की रियासत का इतिहास काकतीय राजवंश से जुड़ा है। परंपरागत मान्यता के अनुसार 14वीं शताब्दी में अन्नमदेव ने यहां शासन की स्थापना की थी। वारंगल के काकतीय शासक प्रतापरुद्र द्वितीय से उनका संबंध बताया जाता है। जगदलपुर की राजपरंपरा और बस्तर दशहरा आज भी इस क्षेत्र की विशिष्ट पहचान हैं।

कांकेर

कांकेर की राजपरंपरा सोमवंशी और स्थानीय राजवंशों से जुड़ी मानी जाती है। बस्तर और रायपुर के बीच स्थित इस रियासत की अपनी प्रशासनिक व्यवस्था और सांस्कृतिक परंपराएं रही हैं।

नांदगांव

नांदगांव का इतिहास महंत घासीदास से जुड़ा है। वर्ष 1865 में अंग्रेजी शासन से मिली सनद के बाद यह क्षेत्र महत्वपूर्ण सामंती रियासत के रूप में स्थापित हुआ।

खैरागढ़

खैरागढ़ की पहचान उसके ऐतिहासिक राजमहल से आगे बढ़कर कला और संगीत के क्षेत्र तक पहुंचती है। वर्ष 1956 में स्थापित इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय इसी महल में संचालित है। शास्त्रीय संगीत, नृत्य और ललित कलाओं के संरक्षण में इस संस्थान का विशेष योगदान है।

छुईखदान

छुईखदान की रियासत का इतिहास ग्रामीण और कृषि आधारित सामाजिक व्यवस्था से जुड़ा रहा है। यहां के पुराने अभिलेख तत्कालीन राजस्व व्यवस्था और स्थानीय प्रशासन को समझने में उपयोगी हो सकते हैं।

कवर्धा

कवर्धा की शाही पहचान उसके राजमहल से जुड़ी है, जबकि भोरमदेव मंदिर समूह इस क्षेत्र की प्राचीन स्थापत्य विरासत का महत्वपूर्ण उदाहरण है। यहां राजसत्ता और धार्मिक परंपराओं का अनूठा संगम देखने को मिलता है।

रायगढ़

रायगढ़ का योगदान कला और संगीत के क्षेत्र में विशेष रहा है। राजा चक्रधर सिंह के संरक्षण में कथक की रायगढ़ शैली विकसित हुई। चक्रधर समारोह के माध्यम से यह सांस्कृतिक विरासत आज भी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाए हुए है।

सारंगढ़

सारंगढ़ की ऐतिहासिक पहचान उसके राजमहल, राजपरिवार की वंशावली और पुराने पारिवारिक दस्तावेजों में छिपी है। वहीं सक्ती की रियासत का प्रभाव कृषि, स्थानीय व्यापार और आसपास के सामाजिक जीवन से जुड़ा रहा है।

सरगुजा

सरगुजा की राजपरंपरा यहां के आदिवासी समाज, धार्मिक मान्यताओं और सांस्कृतिक विविधता के साथ विकसित हुई। इसके अलावा उदयपुर, जशपुर, कोरिया और चांगभखार की रियासतें उत्तरी छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक और प्रशासनिक विकास की महत्वपूर्ण कड़ियां रही हैं। वर्ष 1905 में इन क्षेत्रों में प्रशासनिक पुनर्गठन के तहत बंगाल से सेंट्रल प्रोविंसेज में शामिल किए जाने का इतिहास भी महत्वपूर्ण है। चांगभखार क्षेत्र की पहचान रामगढ़ की प्राचीन नाट्यशाला जैसी पुरातात्विक धरोहरों से भी जुड़ती है।



स्वच्छता के राष्ट्रीय मंच पर चमका छत्तीसगढ़

छोटे शहर बिल्हा ने देश में रचा कीर्तिमान, बिल्हा को 20 हजार से कम आबादी वाले शहरों में पहला स्थान

नदी तटों की स्वच्छता में बिलासपुर देश में दूसरे पायदान पर; रायपुर को राज्य में सर्वश्रेष्ठ नगरीय निकाय का सम्मान

छत्तीसगढ़ के नगरीय विकास और स्वच्छता अभियान को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के परिणामों में प्रदेश के तीन शहरों ने अलग-अलग श्रेणियों में उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय सम्मान हासिल किया है। बिलासपुर जिले की नगर पंचायत बिल्हा ने 20 हजार से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त कर यह साबित किया है कि बेहतर प्रबंधन और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी के दम पर छोटे शहर भी बड़े उदाहरण पेश कर सकते हैं। वहीं, नदी तटों की स्वच्छता और व्यवस्थापन में बिलासपुर को राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान मिला है।

राजधानी रायपुर को प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ शहर के रूप में सम्मानित किया गया है। इन उपलब्धियों ने प्रदेश के नगरीय निकायों में चल रहे स्वच्छता प्रयासों को नई प्रतिष्ठा दी है। खास बात यह है कि सम्मान केवल बड़े नगर निगमों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एक छोटी नगर पंचायत ने भी राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इससे स्थानीय निकायों के सामने स्वच्छता प्रबंधन के नए मानक स्थापित करने की संभावना मजबूत हुई है।

नदी तटों की स्वच्छता में बिलासपुर ने बनाई राष्ट्रीय पहचान

बिलासपुर को स्वच्छ रिवर फ्रंट टाउन श्रेणी में देशभर में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। नदी किनारे बसे शहरों के लिए स्वच्छता बनाए रखना सामान्य नगरीय सफाई से अलग चुनौती है। इसमें नदी तटों का संरक्षण, आसपास के क्षेत्रों में कचरे का प्रबंधन, सार्वजनिक स्थलों की साफ-सफाई और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना शामिल है। इस श्रेणी में मिला सम्मान बिलासपुर की नगरीय व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। साथ ही यह जिम्मेदारी भी बढ़ाता है कि नदी तटों की स्वच्छता को किसी सर्वेक्षण या पुरस्कार तक सीमित रखने के बजाय स्थायी शहरी प्रबंधन का हिस्सा बनाया जाए। रायपुर को मिला प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ शहर का सम्मान राजधानी रायपुर ने भी स्वच्छता के क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत रखी है। राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धा में रायपुर नगर निगम को पहला स्थान मिला है। इससे पहले स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में भी रायपुर ने 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में देशभर में चौथा स्थान हासिल किया था। उस सर्वेक्षण में रायपुर को कुल 12,500 अंकों में से 11,996 अंक मिले थे। कचरा मुक्त शहर प्रमाणीकरण और खुले में शौच मुक्त व्यवस्था के मूल्यांकन में भी नगर निगम ने निर्धारित 2,500 में से पूरे अंक हासिल किए थे। इस प्रदर्शन ने राजधानी को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत पहचान दिलाई थी।

बिल्हा की कामयाबी ने छोटे शहरों के लिए पेश की मिसाल

राष्ट्रीय स्तर पर बिल्हा को मिला पहला स्थान इस उपलब्धि का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। सीमित आबादी और संसाधनों वाले नगरों के बीच प्रतिस्पर्धा में शीर्ष स्थान हासिल करना इस बात का संकेत है कि स्वच्छता के लिए केवल बड़े बजट या विशाल प्रशासनिक ढांचे की जरूरत नहीं होती। योजनाबद्ध कार्यप्रणाली, नियमित निगरानी और स्थानीय लोगों का सहयोग भी शहर की तस्वीर बदल सकता है। बिल्हा की सफलता से यह संदेश भी सामने आता है कि स्वच्छता अभियान को केवल सफाई कर्मचारियों की जिम्मेदारी मानने के बजाय सामुदायिक दायित्व के रूप में विकसित करना जरूरी है। घरों से कचरा उठाने, उसका उचित निस्तारण करने और सार्वजनिक स्थलों को साफ रखने जैसी व्यवस्थाओं में निरंतरता ही ऐसे परिणामों का आधार बनती है।



43 मानकों पर परखी गई देश के शहरों की व्यवस्था

स्वच्छ सर्वेक्षण का दसवां संस्करण देश के नगरीय निकायों के लिए व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया लेकर आया। इसमें 4,751 से अधिक शहरों को शामिल किया गया और 10 प्रमुख क्षेत्रों के 43 संकेतकों के आधार पर उनकी स्थिति का आकलन हुआ। मूल्यांकन में घर-घर कचरा संग्रहण, कचरे का पृथक्करण, ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक निस्तारण, सार्वजनिक स्थानों की सफाई, स्वच्छता सुविधाएं, मलजल प्रबंधन, नागरिकों की भागीदारी और सफाई कर्मचारियों के कल्याण जैसे विषयों को महत्व दिया गया। देशभर में तीन हजार से अधिक प्रशिक्षित मूल्यांकनकर्ताओं ने शहरों का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया। पूरी प्रक्रिया में डिजिटल तकनीक और जीपीएस आधारित निगरानी का इस्तेमाल किया गया। इससे मूल्यांकन को अधिक पारदर्शी और जमीनी स्थिति के अनुरूप बनाने का प्रयास किया गया। इस संस्करण की थीम 'स्वच्छता की नई पहल, बढ़ाएं हाथ, करें सफाई साथ' रखी गई थी।

सामूहिक प्रयासों को मिला राष्ट्रपति के हाथों सम्मान

नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने विजेता नगरीय निकायों को सम्मानित किया। छत्तीसगढ़ की ओर से उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव, विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा और संबंधित नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों तथा अधिकारियों ने पुरस्कार ग्रहण किए। समारोह में रायपुर की महापौर मीनल चौबे, बिलासपुर की महापौर पूजा विधानी और बिल्हा नगर पंचायत की अध्यक्ष वेदना जेंड्रे सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। रायपुर नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा और बिलासपुर नगर निगम आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे भी इस उपलब्धि के साक्षी बने। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर तथा केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू की मौजूदगी में प्रदेश के नगरीय निकायों को यह सम्मान प्रदान किया गया। इस बार पुरस्कार वितरण की व्यवस्था में सफाई कर्मचारियों और जमीनी स्तर पर काम करने वाले कर्मियों को भी विशेष महत्व दिया गया। प्रत्येक विजेता शहर से चार प्रतिनिधियों को मंच पर बुलाया गया, जिनमें सफाई मित्र, स्वच्छता निरीक्षक, पर्यवेक्षक और स्वच्छता मिशन से जुड़े अधिकारी शामिल थे। इससे यह संदेश देने की कोशिश की गई कि शहर की स्वच्छता के पीछे केवल प्रशासनिक नेतृत्व नहीं, बल्कि प्रतिदिन मैदान में काम करने वाले कर्मचारियों की मेहनत भी निर्णायक होती है।

सामूहिक संकल्प का परिणाम: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेश के तीनों नगरीय निकायों की उपलब्धि पर प्रसन्नता जताते हुए नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और स्वच्छता कर्मियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर मिला यह सम्मान प्रदेश के शहरों में हो रहे सकारात्मक बदलाव और स्वच्छता के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रमाण है। मुख्यमंत्री के अनुसार, बिल्हा का राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष स्थान हासिल करना, बिलासपुर का नदी तटवर्ती शहरों की श्रेणी में दूसरा स्थान प्राप्त करना और रायपुर का राज्य में अग्रणी रहना पूरे प्रदेश के लिए गौरव की बात है। उन्होंने स्वच्छता को केवल रैंकिंग तक सीमित न रखते हुए इसे नागरिकों की जीवनशैली और शहरों की स्थायी पहचान बनाने पर जोर दिया।



बेहतर नगरीय प्रबंधन की दिशा में बढ़ी जिम्मेदारी: साव

उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने इस सफलता को नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, सफाई कर्मचारियों और आम नागरिकों के साझा प्रयासों का परिणाम बताया। उन्होंने विशेष रूप से बिल्हा की उपलब्धि का उल्लेख करते हुए कहा कि छोटे नगर भी बेहतर कार्यप्रणाली, प्रतिबद्धता और जनभागीदारी के जरिए देश में अपनी अलग पहचान बना सकते हैं। प्रदेश के तीन निकायों को मिले सम्मान से नगरीय प्रशासन की कार्यप्रणाली को प्रोत्साहन जरूर मिला है, लेकिन इसके साथ आगे की चुनौतियां भी जुड़ी हैं। स्वच्छता की उपलब्धियों को लंबे समय तक कायम रखना, कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण को मजबूत करना, नदी तटों का संरक्षण करना और सफाई व्यवस्था में नागरिकों की भागीदारी बढ़ाना ऐसे विषय हैं, जिन पर निरंतर काम करना होगा। दरअसल, किसी शहर की वास्तविक स्वच्छता उसकी रैंकिंग से अधिक वहां रहने वाले लोगों के रोजमर्रा के अनुभव में दिखाई देती है। साफ सड़कें, व्यवस्थित कचरा संग्रहण, स्वच्छ जल स्रोत और बेहतर सार्वजनिक सुविधाएं ही नगरीय प्रबंधन की असली कसौटी हैं। राष्ट्रीय पुरस्कारों ने छत्तीसगढ़ के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोले हैं। अब चुनौती इन उपलब्धियों को स्थायी व्यवस्था में बदलने की है, ताकि स्वच्छता किसी प्रतियोगिता का परिणाम नहीं, बल्कि प्रदेश के हर शहर की सामान्य पहचान बन सके।





सरेंडर से सियासी शक्ति प्रदर्शन तक

अमित बघेल ने छत्तीसगढ़ की राजनीति को दिया नए समीकरणों पर विचार का संकेत

अदालत में आत्मसमर्पण के दौरान समर्थकों की भीड़ और नारों ने कानूनी घटनाक्रम को राजनीतिक चर्चा का विषय बनाया। क्षेत्रीय अस्मिता, सामाजिक विवाद और छत्तीसगढ़िया पहचान की राजनीति के बीच अमित बघेल की सक्रियता ने प्रदेश के स्थापित राजनीतिक दलों के सामने भी कई सवाल खड़े किए हैं। छत्तीसगढ़ की राजनीति में कुछ घटनाएं अपने कानूनी या प्रशासनिक परिणामों से आगे निकलकर राजनीतिक संदेश देने लगती हैं। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के प्रमुख और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के अध्यक्ष अमित बघेल का रायपुर न्यायालय में आत्मसमर्पण भी इसी दृष्टि से चर्चा का विषय बना है। तीन महीने की अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने के बाद अदालत में उनकी पेशी और आत्मसमर्पण एक न्यायिक प्रक्रिया थी, लेकिन न्यायालय परिसर के बाहर जुटे समर्थकों की भीड़, नारेबाजी और संगठन की सक्रिय मौजूदगी ने इस घटनाक्रम को राजनीतिक अर्थ भी दे दिया।

इस पूरे घटनाक्रम को केवल किसी नेता के कानूनी मामले तक सीमित करके देखना पर्याप्त नहीं होगा। इसके पीछे छत्तीसगढ़िया अस्मिता की राजनीति, क्षेत्रीय संगठनों की बढ़ती सक्रियता, सामाजिक समूहों के बीच संवेदनशीलता और राज्य के प्रमुख राजनीतिक दलों से अलग अपनी पहचान बनाने की कोशिश जैसे कई पहलू जुड़े हैं। अमित बघेल के सरेंडर के दौरान दिखाई गई संगठनात्मक मौजूदगी ने यह सवाल भी खड़ा किया है कि क्या छत्तीसगढ़ की राजनीति में क्षेत्रीय पहचान आधारित राजनीति के लिए एक अलग स्थान बनाने की कोशिश तेज हो रही है? अमित बघेल के न्यायालय में आत्मसमर्पण के दौरान समर्थकों की मौजूदगी ने उनके संगठन की सक्रियता का सार्वजनिक प्रदर्शन जरूर किया है। इससे यह संकेत मिला है कि कानूनी विवाद के बावजूद उनका समर्थक आधार पूरी तरह निष्क्रिय नहीं हुआ है। लेकिन इस घटनाक्रम को राजनीतिक सफलता या भविष्य की चुनावी संभावनाओं का प्रमाण मानना जल्दबाजी होगी। आगे तीन प्रश्न उनकी राजनीति की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण होंगे। पहला, क्या छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना अपने आंदोलन को केवल विरोध और प्रदर्शन से आगे ले जाकर रोजगार, शिक्षा, कृषि, स्थानीय उद्योग और भाषा जैसे मुद्दों पर ठोस कार्यक्रम तैयार करेगी? दूसरा, क्या जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी अपने संगठन का विस्तार प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों तक कर पाएगी? तीसरा, क्या अमित बघेल अपनी क्षेत्रीय राजनीति को सामाजिक सद्भाव और सभी समुदायों के सम्मान के साथ आगे बढ़ा सकेंगे? दरअसल, रायपुर न्यायालय के बाहर जुटी भीड़ ने अमित बघेल की राजनीतिक मौजूदगी को फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है, लेकिन भीड़ से जनादेश तक पहुंचने का रास्ता लंबा है। सरेंडर की घटना ने एक राजनीतिक संदेश जरूर दिया है कि छत्तीसगढ़िया अस्मिता के नाम पर सक्रिय संगठन अपनी अलग पहचान बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि यह सक्रियता किसी व्यापक क्षेत्रीय राजनीतिक विकल्प का स्वरूप लेती है या फिर आंदोलन और विवादों तक ही सीमित रहती है। यही अंतर अमित बघेल की आगे की राजनीतिक भूमिका और छत्तीसगढ़ की क्षेत्रीय राजनीति में उनके स्थान को समझने की असली कसौटी बनेगा।

कानूनी प्रक्रिया और राजनीतिक संदेश का अंतर

अमित बघेल के मामले में कानूनी घटनाक्रम की अपनी गंभीरता है। 26 अक्टूबर 2025 को रायपुर के वीआईपी चौक पर छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा को क्षति पहुंचाने की घटना के बाद विवाद शुरू हुआ था। इसके विरोध में छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के कार्यकर्ता सक्रिय हुए। इसी घटनाक्रम के दौरान अग्रवाल और सिंधी समाज के संबंध में अमित बघेल की कथित टिप्पणियों ने विवाद को व्यापक सामाजिक और कानूनी रूप दे दिया। उनके खिलाफ अलग-अलग थानों में कुल 14 प्राथमिकी दर्ज होने की जानकारी सामने आई। दिसंबर 2025 में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। इस मामले में एक महत्वपूर्ण कानूनी तथ्य यह भी है कि बिलासपुर उच्च न्यायालय ने नियमित जमानत देने से इनकार किया था, लेकिन तीन मामलों में तीन महीने की सीमित अवधि के लिए अस्थायी जमानत अथवा पैरोल की राहत प्रदान की थी। इस राहत के साथ रायपुर जिले में प्रवेश को लेकर भी शर्त लगाई गई थी। निर्धारित अवधि पूरी होने पर न्यायालय में आत्मसमर्पण करना उसी न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा था। इसलिए सरेंडर को न तो किसी राजनीतिक विजय के रूप में देखा जा सकता है और न ही इसे न्यायिक मामले का अंतिम निष्कर्ष माना जा सकता है। लेकिन राजनीति में किसी घटनाक्रम का प्रभाव केवल उसकी कानूनी व्याख्या से तय नहीं होता। यह भी देखा जाता है कि संबंधित व्यक्ति उस परिस्थिति में अपने समर्थकों, संगठन और व्यापक समाज के सामने किस तरह उपस्थित होता है। अमित बघेल के मामले में यही पहलू महत्वपूर्ण हो जाता है। अदालत में आत्मसमर्पण के लिए पहुंचने वाले नेता के साथ समर्थकों की बड़ी मौजूदगी ने यह संदेश देने की कोशिश की कि कानूनी मुश्किलों के बावजूद संगठन की सक्रियता समाप्त नहीं हुई है।

भीड़ का संदेश: नेता के साथ संगठन भी मौजूद है

अदालत परिसर के बाहर जुटी भीड़ को केवल भावनात्मक समर्थन की सामान्य अभिव्यक्ति मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। किसी राजनीतिक या सामाजिक संगठन के लिए ऐसे अवसर अपनी संगठनात्मक क्षमता प्रदर्शित करने का माध्यम भी बनते हैं। समर्थकों की नारेबाजी और सामूहिक उपस्थिति के जरिए यह बताने का प्रयास दिखाई देता है कि नेतृत्व के सामने संकट आने पर संगठन उसके साथ खड़ा है। अमित बघेल के लिए इस शक्ति प्रदर्शन का एक राजनीतिक पक्ष यह भी है कि उनके समर्थकों को यह अनुभव कराया जाए कि उनका नेतृत्व सामाजिक और राजनीतिक दबाव के बावजूद सक्रिय है। किसी नेता की सार्वजनिक छवि केवल उसके भाषणों या चुनावी गतिविधियों से नहीं बनती। उसके समर्थकों की निष्ठा, संगठन की निरंतरता और प्रतिकूल परिस्थितियों में उसकी सार्वजनिक मौजूदगी भी उस छवि को प्रभावित करती है। हालांकि, भीड़ का आकार अपने आप में जनसमर्थन का निर्णायक प्रमाण नहीं होता। किसी न्यायालय परिसर में जुटे समर्थकों की संख्या से पूरे प्रदेश की राजनीतिक राय या चुनावी समर्थन का अनुमान लगाना उचित नहीं होगा। इसके लिए संगठन का जमीनी विस्तार, सदस्यता, विभिन्न क्षेत्रों में सक्रियता, स्थानीय मुद्दों पर उसका काम और चुनावी प्रदर्शन जैसे अनेक पहलुओं का मूल्यांकन जरूरी है।

भाजपा और कांग्रेस के सामने क्षेत्रीय राजनीति का सवाल

अमित बघेल की सक्रियता का राजनीतिक असर समझने के लिए भाजपा और कांग्रेस, दोनों की स्थिति का विश्लेषण जरूरी है। छत्तीसगढ़ में इन दोनों दलों का राजनीतिक आधार व्यापक है, लेकिन क्षेत्रीय अस्मिता के सवाल पर दोनों के सामने अलग-अलग चुनौतियां हैं।

भाजपा के लिए चुनौती

भाजपा की राजनीति में राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक पहचान और हिंदुत्व जैसे मुद्दों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। छत्तीसगढ़ में सत्ता में होने के कारण उसके सामने विकास, प्रशासन और स्थानीय आकांक्षाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी भी है। छत्तीसगढ़िया अस्मिता का प्रश्न भाजपा के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि स्थानीय भाषा, संस्कृति, परंपरा और महापुरुषों के सम्मान से जुड़े विषय किसी एक राजनीतिक विचारधारा तक सीमित नहीं हैं। अमित बघेल जैसे क्षेत्रीय नेतृत्व की सक्रियता भाजपा के सामने यह सवाल रखती है कि स्थानीय पहचान के मुद्दों पर उसका राजनीतिक और संगठनात्मक संवाद कितना प्रभावी है। यदि क्षेत्रीय संगठन इन मुद्दों को लगातार उठाते हैं तो स्थापित दलों को भी अपनी नीतियों और राजनीतिक संवाद में स्थानीय अपेक्षाओं को पर्याप्त स्थान देना होगा। हालांकि, इस मामले में भाजपा के लिए एक दूसरा पक्ष भी है। अग्रवाल और सिंधी समाज से जुड़ा विवाद सामाजिक सौहार्द का विषय बन चुका है। इन समुदायों की आपत्तियों और भावनाओं को नजरअंदाज करके क्षेत्रीय अस्मिता की राजनीति का विश्लेषण अधूरा रहेगा। किसी भी राजनीतिक संगठन के लिए स्थानीय पहचान का सम्मान और दूसरे समुदायों के प्रति सम्मानजनक व्यवहार साथ-साथ चलना जरूरी है।

कांग्रेस के लिए चुनौती

कांग्रेस के लिए यह विषय कुछ अलग तरह की राजनीतिक चुनौती प्रस्तुत करता है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में छत्तीसगढ़िया संस्कृति, भाषा, खानपान, तीज-त्योहार और स्थानीय परंपराओं को राजनीतिक विमर्श में प्रमुखता मिली थी। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में भी क्षेत्रीय अस्मिता एक महत्वपूर्ण मुद्दा रही थी। लेकिन इस विचार को किसी एक राजनीतिक दल की स्थायी संपत्ति नहीं माना जा सकता। अमित बघेल का अलग क्षेत्रीय राजनीतिक मंच इसी खाली जगह को अपने तरीके से भरने की कोशिश कर सकता है। कांग्रेस के लिए चुनौती यह होगी कि वह स्थानीय पहचान के सवाल पर अपनी राजनीतिक भूमिका को किस तरह परिभाषित करती है। यदि क्षेत्रीय मुद्दों पर उसका संवाद कमजोर होता है तो अन्य संगठन उस विमर्श में अपनी जगह बनाने का प्रयास कर सकते हैं। दूसरी ओर, अमित बघेल के विवादित बयानों से जुड़ा मामला कांग्रेस के लिए भी संवेदनशील है। सामाजिक सद्भाव और समुदायों के सम्मान का प्रश्न किसी भी दल के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए क्षेत्रीय अस्मिता का समर्थन करने और विवादित टिप्पणियों का राजनीतिक समर्थन करने के बीच अंतर बनाए रखना आवश्यक होगा।



छत्तीसगढ़िया अस्मिता की राजनीति ही आधार

अमित बघेल की राजनीति को समझने के लिए छत्तीसगढ़िया अस्मिता के प्रश्न को समझना होगा। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद से ही यहां क्षेत्रीय पहचान, भाषा, संस्कृति, स्थानीय संसाधनों और रोजगार में स्थानीय लोगों की भागीदारी जैसे विषय राजनीतिक विमर्श का हिस्सा रहे हैं। अलग-अलग राजनीतिक दलों ने समय-समय पर इन मुद्दों को अपने राजनीतिक एजेंडे में स्थान दिया है। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना इसी क्षेत्रीय चेतना को संगठनात्मक और आंदोलनकारी स्वरूप देने की कोशिश करती रही है। अमित बघेल की राजनीतिक शैली में स्थानीय पहचान और क्षेत्रीय अधिकारों के मुद्दे प्रमुख रहे हैं। उनकी राजनीति का एक पक्ष यह है कि वे उन विषयों को सामने लाते हैं, जिन पर स्थापित राजनीतिक दलों की सक्रियता अवसर सत्ता, चुनाव और तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से बदलती दिखाई देती है। इस विषय पर राष्ट्रीय मीडिया में भी चर्चा हुई है। इंडिया टुडे की नवंबर 2025 की एक विस्तृत रिपोर्ट ने अमित बघेल की राजनीति को छत्तीसगढ़िया अस्मिता के विमर्श और राज्य की बदलती राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में देखा था। रिपोर्ट में क्षेत्रीय पहचान के मुद्दे को प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस और भाजपा के बीच मौजूद व्यापक प्रतिस्पर्धा से जोड़कर समझाया गया था। यहां एक बुनियादी सवाल है कि क्या छत्तीसगढ़िया पहचान का मुद्दा केवल भावनात्मक नारों तक सीमित रहेगा या इसे रोजगार, शिक्षा, भाषा, स्थानीय अर्थव्यवस्था और प्रशासन में भागीदारी जैसे ठोस प्रश्नों से जोड़ा जाएगा? अमित बघेल की राजनीतिक प्रासंगिकता का मूल्यांकन भी इसी कसौटी पर होना चाहिए।

खेतों में मेहनत, आंखों में आस

अन्नदाता के विश्वास से समृद्धि की ओर बढ़ता छत्तीसगढ़

कम धान बेचे म घलो पूरा लाभ पाही, किसान के अंगना म खुशहाली आही



छत्तीसगढ़ में धान केवल फसल नहीं, गांवों की जीवनधारा है। खेतों में लहलहाती बालियों के साथ किसान के सपने भी आकार लेते हैं। बच्चों की पढ़ाई, परिवार का स्वास्थ्य, घर की जरूरतें और अगली फसल की तैयारी इन्हीं सपनों का हिस्सा हैं। इसलिए किसान को मिलने वाला आर्थिक सहयोग पूरे परिवार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संबल देता है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में किसान केंद्रित पहल इसी विश्वास को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं।



विजय मानिकपुरी

मेहनत का मान, खेती को संबल

कृषक उन्नति योजना के नवीन दिशा-निर्देश किसानों के लिए महत्वपूर्ण हैं। खरीफ वर्ष 2026 से लागू व्यवस्था में धान के बोए गए सत्यापित पात्र रकबे पर प्रति एकड़ 13 हजार 839 रुपये की आदान सहायता का प्रावधान है। विशेष बात यह है कि निर्धारित अधिकतम सीमा से कम धान बेचने पर भी संबंधित पात्र रकबे की पूरी सहायता मिलेगी। यदि पात्र किसान एक एकड़ में धान बोकर 21 क्विंटल की अधिकतम सीमा के मुकाबले 15 क्विंटल बेचता है, तब भी उसे उस सत्यापित पात्र रकबे के लिए पूरी निर्धारित सहायता मिलेगी। खेती का खर्च खेत की तैयारी, बीज, खाद, सिंचाई और देखभाल से जुड़ा होता है। उत्पादन में अंतर तथा घरेलू उपयोग के लिए धान रखने की जरूरत को देखते हुए रकबा आधारित सहायता उपयोगी कदम है।

खरीदी का विस्तार, बढ़ती भागीदारी

प्रदेश में धान खरीदी से जुड़ने वाले किसानों की संख्या बढ़ी है। वर्ष 2015 में पंजीकृत किसान 13.17 लाख थे, जो वर्ष 2025-26 में बढ़कर 27.53 लाख हो गए। इसी अवधि में पंजीकृत रकबा 21.26 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 33 लाख हेक्टेयर पहुंचा। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में 25 लाख 24 हजार से अधिक किसानों से 141.04 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया। किसानों को समर्थन मूल्य के रूप में 33,431 करोड़ रुपये और आदान सहायता के रूप में 10,292 करोड़ रुपये दिए गए। वर्ष 2026-27 में 360 नए खरीदी केंद्र खोलने का निर्णय किसानों का परिवहन खर्च और समय बचाने में सहायक होगा।

विविध फसलों से नए अवसर

कृषि की मजबूती के लिए धान के साथ दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी और रागी जैसी फसलों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। धान के स्थान पर दूसरी फसल लेने पर प्रति एकड़ 11 हजार रुपये तथा चयनित अन्य फसलों के लिए 10 हजार रुपये की प्रोत्साहन सहायता का प्रावधान है। स्थानीय मिट्टी, पानी और बाजार के अनुरूप फसल चयन किसानों के लिए आय के नए अवसर खोल सकता है। गन्ना खरीदी दर 355 रुपये से बढ़ाकर 425 रुपये प्रति क्विंटल करने का निर्णय भी उत्पादकों को अतिरिक्त आर्थिक लाभ देगा। वहीं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा जैसी व्यवस्थाएं खेती की जरूरतों तथा जोखिमों के बीच सहयोग का आधार हैं।

सही जानकारी से पूरा लाभ

योजनाओं की सफलता के लिए पात्र किसानों तक सही जानकारी पहुंचना आवश्यक है। कृषक उन्नति योजना में एग्रीस्टैक पंजीयन और निर्धारित पात्रता जरूरी है। बोए गए रकबे का सत्यापन डिजिटल क्रॉप सर्वे से होगा। डेटा उपलब्ध नहीं होने पर कलेक्टर की अनुमति से गिरदावरी के आधार पर सत्यापन किया जाएगा। सहायता का आधार से लिंक बैंक खातों में एकमुश्त प्रत्यक्ष हस्तांतरण किसानों को अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार राशि उपयोग करने का अवसर देगा। विभागों और समितियों का सहयोग प्रक्रिया को सहज बनाएगा। छत्तीसगढ़ को 'धान का कटोरा' बनाने में पीढ़ियों का श्रम समाया है। बेहतर मूल्य, समय पर भुगतान, सिंचाई, तकनीक और बाजार की सुविधा से यही श्रम समृद्धि में बदलेगा। प्रत्येक पात्र किसान तक लाभ पहुंचे, तभी खेतों की हरियाली घर-आंगन की खुशहाली बनेगी।

खेत म लहराही धान,
किसान के बढ़ही मान,
अन्नदाता के खुशहाली ले,
खुशहाल होही छत्तीसगढ़ के गांव!

दीपावली मिलन में दिखी सियासी सौहार्द की झलक





छत्तीसगढ़ में दीपावली के अवसर पर राजनीतिक हलकों में भी मेल-मिलाप और आत्मीयता का माहौल नजर आया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अलग-अलग दीपावली मिलन समारोह आयोजित किए। दोनों आयोजनों में जनप्रतिनिधियों, पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों ने उत्साह के साथ शिरकत की। आतिशी रोशनी और त्योहार की खुशियों के बीच नेताओं ने लोगों से मुलाकात कर शुभकामनाएं साझा कीं। राजनीतिक मतभेदों से इतर इन आयोजनों ने सामाजिक सद्भाव, आपसी संवाद और लोकतांत्रिक परंपराओं में व्यक्तिगत संबंधों की अहमियत को भी रेखांकित किया।



युवा शक्ति का नया शिखर

पाकिस्तान को आखिरी गेंद पर पछाड़ भारत ने नौवीं बार पहना एशिया का ताज

पांच साल का इंतजार, तीन टूर्नामेंट की निराशा और पिछले फाइनल की करारी हार का जवाब। भारतीय युवा ब्रिगेड ने 338 रन के पहाड़ जैसे लक्ष्य को आखिरी गेंद पर पार कर अंडर-19 एशिया कप का रिकॉर्ड नौवां खिताब जीत लिया। मोहित उल्वा, मनल चौहान, आर्यवीर सहवाग और कप्तान लक्ष्य राजेश रायचंदानी जैसे खिलाड़ियों ने जिस साहस और प्रतिभा का परिचय दिया, वह भारतीय क्रिकेट के भविष्य के लिए बड़ा संकेत है। यह जीत केवल एक ट्रॉफी नहीं, बल्कि अगली पीढ़ी के क्रिकेटरों के आत्मविश्वास, कौशल और बड़े मंच पर दबाव झेलने की क्षमता का ऐलान है। ओमान के अल अमरात मैदान पर भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया अंडर-19 एशिया कप 2026 का फाइनल भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक यादगार अध्याय बन गया। मुकाबले में उतार-चढ़ाव इतने थे कि आखिरी ओवर तक किसी को नतीजे का भरोसा नहीं था। पाकिस्तान ने 337 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। जवाब में भारतीय टीम एक समय 252 रन पर आठ विकेट गंवा चुकी थी। हार सामने खड़ी दिखाई दे रही थी, लेकिन युवा खिलाड़ियों ने हार मानने से इनकार कर दिया। दसवें नंबर पर उतरे मोहित उल्वा ने नाबाद 49 रन की विस्फोटक पारी खेली और अंतिम गेंद पर चौका लगाकर भारत को एक विकेट से जीत दिला दी। इस जीत के साथ भारत ने पांच साल बाद अंडर-19 एशिया कप का खिताब वापस हासिल किया। इससे भी बड़ी बात यह रही कि भारतीय टीम ने नौवीं बार ट्रॉफी जीतकर टूर्नामेंट के इतिहास में अपनी सर्वोच्चता को और मजबूत कर दिया। पाकिस्तान को उसी के पिछले खिताबी मुकाबले की जीत के बाद इस बार निर्णायक मंच पर हराना भारतीय युवा टीम के लिए उपलब्धि के साथ जवाब भी था।

हार की दहलीज से चैंपियन बनने तक

पाकिस्तान की पारी में उस्मान खान ने 107 रन बनाकर भारतीय गेंदबाजों को कड़ी चुनौती दी। अब्दुल कादिर ने 80 और कप्तान फरहान यूसुफ ने 63 रन की पारी खेली। इन तीनों के दम पर पाकिस्तान ने नौ विकेट पर 337 रन बनाए। भारत की ओर से काव्या पटेल ने चार और चिगुरुपति वेंकट ने तीन विकेट लेकर पाकिस्तान को इससे भी बड़े स्कोर तक पहुंचने से रोका। 338 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को आर्यवीर सहवाग ने 58 रन बनाकर अच्छी शुरुआत दी। कप्तान लक्ष्य राजेश रायचंदानी ने 80 रन की जिम्मेदार पारी खेली। लेकिन मध्यक्रम के विकेट लगातार गिरने से भारत की स्थिति कमजोर हो गई। जब आठ विकेट गिर चुके थे, तब जीत की उम्मीद बहुत कम बची थी। ऐसे समय में मनल चौहान और मोहित उल्वा ने नौवें विकेट के लिए 57 रन जोड़कर मैच का रुख बदल दिया। मनल ने 32 गेंदों पर 47 रन बनाए, जबकि मोहित ने केवल 26 गेंदों में पांच चौके और तीन छक्के जड़ते हुए नाबाद 49 रन बनाए। आखिरी ओवर में भारत को आठ रन चाहिए थे। अंतिम गेंद पर तीन रन की जरूरत थी और मोहित ने चौका लगाकर इतिहास रच दिया। इस जीत की खूबसूरती यह थी कि भारत को केवल शीर्ष क्रम के स्थापित बल्लेबाजों ने नहीं जिताया। निचले क्रम के खिलाड़ियों ने भी जिम्मेदारी उठाई। मोहित की पारी बताती है कि आधुनिक क्रिकेट में बल्लेबाजी का कौशल किसी एक क्रम तक सीमित नहीं रह गया है। दबाव में सही फैसला लेना, गेंद की दिशा समझना और मैच की मांग के अनुसार खेलना ही बड़े खिलाड़ी की पहचान बनता है।

आर्यवीर सहवाग से मोहित उल्वा तक, भविष्य की नई तस्वीर

इस टूर्नामेंट में आर्यवीर सहवाग का प्रदर्शन विशेष चर्चा का विषय रहा। उन्होंने पांच पारियों में 361 रन बनाए और प्रतियोगिता के सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। उनके खाते में एक शतक और तीन अर्धशतक रहे। फाइनल में 58 रन की पारी ने भी भारत की जीत की नींव तैयार की। पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने युवा टीम को बधाई देते हुए आर्यवीर के प्रदर्शन की सराहना की। उनके पिता वीरेंद्र सहवाग ने भी खिलाड़ियों के संघर्ष और जुझारूपन की प्रशंसा की। आर्यवीर के साथ कप्तान लक्ष्य की 80 रन की पारी, मनल चौहान की उपयोगी बल्लेबाजी और मोहित उल्वा का निर्णायक प्रदर्शन इस टीम की अलग-अलग ताकतों को सामने लाता है। विकेटकीपर अन्वय द्रविड़ जैसे खिलाड़ियों की मौजूदगी भी इस बात का संकेत है कि नई पीढ़ी में क्रिकेट की विरासत और नई सोच साथ-साथ आगे बढ़ रही है। हालांकि, किसी खिलाड़ी की भविष्य की सफलता का फैसला एक टूर्नामेंट से नहीं किया जा सकता। निरंतर प्रदर्शन, तकनीकी सुधार और घरेलू क्रिकेट में अनुभव ही उन्हें अगले स्तर तक पहुंचाएंगे।





पांच साल का इंतजार और पिछली हार का जवाब

भारतीय टीम ने पिछली बार 2021 में श्रीलंका को नौ विकेट से हराकर यह खिताब जीता था। इसके बाद लगातार तीन संस्करणों में टीम को निराशा का सामना करना पड़ा। 2023 में बांग्लादेश ने सेमीफाइनल में भारत को बाहर कर दिया। 2024 के फाइनल में बांग्लादेश ने 59 रन से हराया। 2025 में पाकिस्तान ने खिताबी मुकाबले में 191 रन की बड़ी जीत दर्ज कर भारत का सपना तोड़ दिया। इन नतीजों ने भारतीय युवा क्रिकेट के सामने एक सवाल खड़ा किया था कि क्या प्रतिभा से भरपूर टीम बड़े मुकाबलों में दबाव झेलने की क्षमता भी विकसित कर पा रही है? 2026 के फाइनल ने इस सवाल का जवाब दिया। इस बार भारतीय टीम ने न केवल बड़े लक्ष्य का पीछा किया, बल्कि उस समय वापसी की जब मुकाबला लगभग हाथ से निकल चुका था। यह जीत पिछले वर्षों की नाकामियों को भुलाने और नई शुरुआत करने का अवसर भी है।

नौ खिताब: भारतीय युवा क्रिकेट की लंबी बादशाहत

अंडर-19 एशिया कप की शुरुआत 1989 में हुई थी। इस प्रतियोगिता ने एशियाई क्रिकेट को युवा प्रतिभाओं की पहचान और विकास का मंच दिया है। भारत ने पहले ही संस्करण में श्रीलंका को हराकर खिताब जीता था। इसके बाद 2003 में भी श्रीलंका को मात देकर ट्रॉफी हासिल की। 2012 में भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल टाई रहा और दोनों टीमों को संयुक्त विजेता घोषित किया गया। इसके बाद भारतीय टीम ने 2013-14 में पाकिस्तान को हराकर खिताब जीता। 2016 और 2018 में श्रीलंका को हराकर ट्रॉफी अपने नाम की। 2019 में बांग्लादेश को मात दी और 2021 में श्रीलंका के खिलाफ जीत दर्ज की। अब 2026 में पाकिस्तान को हराकर भारत ने नौवीं बार यह उपलब्धि हासिल की है। इस तरह भारत ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान और बांग्लादेश से सात खिताब की बढ़त बना ली है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के खाते में दो-दो खिताब हैं, जबकि अफगानिस्तान ने 2017 में पहली बार ट्रॉफी जीती थी। यह रिकॉर्ड केवल जीतों की संख्या नहीं है। यह भारतीय क्रिकेट की उस व्यवस्था का संकेत है, जो लगातार नई प्रतिभाओं को खोजती है, उन्हें प्रतिस्पर्धा का अनुभव देती है और अंतरराष्ट्रीय स्तर के लिए तैयार करती है।

युवा क्रिकेट की असली परीक्षा अब शुरू होगी

अंडर-19 स्तर पर खिताब जीतना बड़ी उपलब्धि है, लेकिन सीनियर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट तक पहुंचने का रास्ता लंबा और चुनौतीपूर्ण होता है। यहां से खिलाड़ियों को फिटनेस, तकनीक, मानसिक मजबूती और लगातार बेहतर प्रदर्शन की कसौटी पर खरा उतरना होगा। कई बार जूनियर स्तर पर चमकने वाले खिलाड़ी आगे चलकर अपेक्षित सफलता हासिल नहीं कर पाते, जबकि कुछ खिलाड़ी अनुभव के साथ विश्व क्रिकेट में अपनी पहचान बनाते हैं। इसलिए इस जीत के बाद सबसे जरूरी है कि इन प्रतिभाओं को सही प्रशिक्षण, घरेलू क्रिकेट में पर्याप्त अवसर और चयन प्रक्रिया में निरंतरता मिले। फाइनल ने भारतीय टीम की कुछ कमियों को भी उजागर किया। 337 रन खर्च करना और लक्ष्य का पीछा करते हुए आठ विकेट गंवा देना बताता है कि गेंदबाजी और मध्यक्रम की स्थिरता पर काम करने की जरूरत है। लेकिन यही किसी युवा टीम की सीखने की प्रक्रिया भी है। जीत के साथ अपनी कमजोरियों को पहचानना ही आगे बढ़ने का सही रास्ता है।

ट्रॉफी से बड़ी उपलब्धि है जीतने का जज्बा

भारत की नौवीं खिताबी जीत ने एक बार फिर साबित किया कि देश में क्रिकेट प्रतिभा की कमी नहीं है। छोटे शहरों, अलग-अलग राज्यों और विविध पृष्ठभूमियों से आने वाले खिलाड़ी अब बड़े मंच पर अपनी छाप छोड़ रहे हैं। भारतीय क्रिकेट का भविष्य केवल किसी एक बड़े नाम या स्टार खिलाड़ी पर निर्भर नहीं है। उसकी असली ताकत ऐसी युवा ब्रिगेड है, जिसमें शीर्ष क्रम से लेकर दसवें नंबर तक मैच जिताने का माद्दा मौजूद है। मोहित उल्वा का आखिरी गेंद पर लगाया गया चौका इस पूरी टीम के जज्बे का प्रतीक बन गया है। पांच साल बाद मिली ट्रॉफी, पिछली हार का जवाब और रिकॉर्ड नौवां खिताब भारतीय युवा क्रिकेट के लिए नई ऊर्जा लेकर आया है। यह जीत बताती है कि अगली पीढ़ी केवल अपने पूर्ववर्तियों की विरासत संभालने नहीं, बल्कि उसमें नए अध्याय जोड़ने के इरादे से मैदान पर उतर रही है।



रंजिश का खौफनाक अंत

बदले की आग में दस साल से झुलसते विनोद ने राजा नायडू के साथ रची साजिश

रात के करीब साढ़े आठ बजे थे। निरंजन पाल घर से निकला तो परिवार को शायद यही लगा होगा कि कुछ देर में लौट आएगा। लेकिन वह रात उसके जीवन की आखिरी रात साबित हुई। 10 नवंबर के बाद निरंजन घर नहीं लौटा। परिवार ने तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। आखिरकार मां ने तेलीबांधा थाने पहुंचकर बेटे की गुमशुदगी की सूचना दी। पुलिस ने मामला दर्ज किया और उसकी तलाश शुरू कर दी। शुरुआत में यह एक युवक के लापता होने का मामला था। किसी को अंदाजा नहीं था कि निरंजन की तलाश पुलिस को रायपुर के कमल विहार के सेक्टर-13 के एक सुनसान हिस्से तक ले जाएगी, जहां उसकी जिंदगी खत्म कर दी गई थी। और इस हत्या के पीछे वजह कोई तात्कालिक विवाद नहीं, बल्कि करीब दस साल से मन में पल रही रंजिश थी। पुलिस के मुताबिक, निरंजन की हत्या विनोद दाडेकर और राजा नायडू ने मिलकर की थी। विनोद को संदेह था कि करीब एक दशक पहले उसके बेटे की हत्या में निरंजन पाल शामिल था। इसी शक ने उसके मन में निरंजन के प्रति ऐसी दुश्मनी पैदा कर दी, जिसका अंत हत्या के रूप में हुआ।

गुमशुदगी की शिकायत से शुरू हुई तलाश

निरंजन पाल 10 नवंबर की रात करीब 8:30 बजे से लापता था। देर तक घर नहीं लौटने पर परिजन परेशान हुए। उसकी मां ने तेलीबांधा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने सूचना मिलने के बाद युवक की पतासाजी शुरू की। आसपास के लोगों से पूछताछ की गई और उन लोगों के बारे में जानकारी जुटाई गई, जिनसे निरंजन का संपर्क हो सकता था। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस ने कुछ संदिग्धों से पूछताछ शुरू की। इसी दौरान राजा नायडू का नाम सामने आया। उससे पूछताछ में मिले सुराग पुलिस को विनोद दाडेकर तक ले गए। पुलिस के मुताबिक, दोनों से पूछताछ के दौरान घटनाक्रम की कड़ियां जुड़ने लगीं। जिस युवक की तलाश गुमशुदगी के आधार पर की जा रही थी, वह अब हत्या के मामले में बदल चुकी थी।





दस साल पुराना शक बना हत्या की वजह

पुलिस की पूछताछ में जो वजह सामने आई, वह इस वारदात का सबसे अहम पहलू थी। विनोद दांडेकर को शक था कि करीब दस साल पहले उसके बेटे की हत्या में निरंजन पाल की भूमिका थी। इस संदेह को लेकर वह लंबे समय से निरंजन के प्रति रंजिश रखे हुए था। समय गुजरता रहा, लेकिन पुलिस के मुताबिक विनोद के मन में पल रहा यह शक खत्म नहीं हुआ। पुरानी घटना की याद और निरंजन के प्रति नाराजगी उसके मन में बनी रही। इसी रंजिश का बदला लेने के लिए उसने राजा नायडू के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई। यहां एक बात गौर करने वाली है कि पुलिस के सामने जो वजह आई, वह विनोद का संदेह था। निरंजन के उसके बेटे की हत्या में शामिल होने की बात को इस आधार पर स्थापित तथ्य नहीं माना जा सकता। लेकिन इसी संदेह को विनोद ने बदले की वजह बनाया और कथित तौर पर एक नई हत्या की साजिश रच डाली।



शराब के बहाने बुलाया फिर दबा दिया गला

पुलिस के अनुसार, विनोद दांडेकर और राजा नायडू ने निरंजन को कमल विहार के सेक्टर-13 के सुनसान इलाके में बुलाया। वहां पहले उसे शराब पिलाई गई। माहौल सामान्य दिखाने के बाद दोनों ने उस पर हमला कर दिया और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी।



शराब के जाम से शुरू हुई मुलाकात का अंत मौत में हुआ। जिस जगह निरंजन को बुलाया गया था, वहां आसपास लोगों की आवाजाही कम थी। आरोपियों ने इसी सुनसान जगह को वारदात के लिए चुना था। पुलिस के सामने आए घटनाक्रम के अनुसार, हत्या के बाद दोनों ने शव को ठिकाने लगाने और अपनी पहचान छिपाने की तैयारी शुरू की। हत्या के बाद उनका अगला मकसद था कि पुलिस को न शव मिले और न ऐसे साक्ष्य, जिनसे उन तक पहुंचा जा सके। इसके लिए उन्होंने मृतक के कपड़े उतारे और उन्हें जला दिया। इसके बाद शव को गटर के मेनहोल में डालकर ऊपर से ढक्कन बंद कर दिया।

शव गटर में, एक्टिवा नदी के पास छिपाई

आरोपियों ने केवल शव छिपाने तक ही अपनी कोशिश सीमित नहीं रखी। निरंजन की एक्टिवा को भी घटनास्थल से दूर ले जाया गया। पुलिस के अनुसार, वाहन को मुजगहन क्षेत्र में बाकल नदी के पास छिपाया गया था। शव और वाहन को अलग-अलग स्थानों पर छिपाने के पीछे मकसद यही था कि जांच करने वालों को दोनों के बीच संबंध जोड़ने में मुश्किल हो। कपड़े जलाकर पहचान से जुड़े साक्ष्य मिटाने और शव को मेनहोल में डालकर ढक्कन बंद करने की कोशिश भी इसी योजना का हिस्सा थी। लेकिन अपराध के बाद साक्ष्य छिपाने की कोशिशें पुलिस की जांच को रोक नहीं सकीं। गुमशुदगी के मामले में जुटाए गए सुरागों ने जांच की दिशा बदल दी। राजा नायडू से मिली जानकारी के बाद पुलिस विनोद दांडेकर तक पहुंची। पूछताछ में दोनों की भूमिका सामने आने के बाद पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझाने का दावा किया।

सुरागों ने खोला राज, आरोपियों की निशानदेही पर बरामदगी

तेलीबांधा पुलिस ने राजा नायडू और विनोद दांडेकर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक, राजा नायडू तेलीबांधा थाने का गुंडा-बदमाश है। दोनों आरोपियों की निशानदेही पर निरंजन पाल का शव बरामद किया गया। इसके अलावा उसके जले हुए कपड़े और एक्टिवा भी जब्त की गई। मामले में हत्या और साक्ष्य मिटाने सहित अन्य संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस आगे की जांच कर रही है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे विचलित करने वाली बात यह है कि हत्या के पीछे करीब दस साल पुराना संदेह बताया जा रहा है। एक ऐसी घटना, जिसमें निरंजन की कथित भूमिका को लेकर विनोद के मन में शक था, उसी शक ने एक और परिवार को उजाड़ दिया। यदि किसी को पुराने अपराध में किसी व्यक्ति की भूमिका पर संदेह था, तो उसका रास्ता कानून और जांच की प्रक्रिया से होकर गुजरना चाहिए था। लेकिन पुलिस के अनुसार, विनोद ने न्याय पाने के बजाय खुद ही बदला लेने का रास्ता चुना। निरंजन के परिवार के लिए यह घटना केवल एक गुमशुदगी का दुखद अंत नहीं, बल्कि उस भरोसे का टूटना भी है कि घर से निकला व्यक्ति लौटकर आएगा। दूसरी ओर, आरोपियों की कथित योजना यह थी कि शव, कपड़े और वाहन अलग-अलग छिपाकर वे वारदात को दबा देंगे। मगर पुलिस की जांच ने उन कड़ियों को जोड़ दिया, जिन्हें मिटाने की कोशिश की गई थी। दस साल पुरानी रंजिश का यह अंत एक बार फिर यही सवाल छोड़ता है कि मन में पाला गया संदेह जब कानून से ऊपर हो जाता है, तो उसका परिणाम केवल एक व्यक्ति की मौत नहीं होता। उसके साथ कई जिंदगियां और परिवार भी उस अपराध की कीमत चुकाने लगते हैं।



मतदाता सूची का महामंथन

एसआईआर ने छत्तीसगढ़ में खड़े किए सवाल, 25 लाख नामों की कटौती पर सियासी संग्राम

मतदाता सूची लोकतंत्र की बुनियादी दस्तावेज है। इसमें दर्ज एक-एक नाम केवल किसी व्यक्ति की पहचान नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में उसकी भागीदारी का अधिकार भी है। इसलिए मतदाता सूची के शुद्धिकरण की कोई भी कवायद जितनी जरूरी है, उतनी ही संवेदनशील भी। विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर इसी उद्देश्य से शुरू किया गया, लेकिन छत्तीसगढ़ में यह प्रक्रिया पारदर्शिता, पात्रता और राजनीतिक निष्पक्षता जैसे सवालों के घेरे में आ गई। लगभग 25 लाख मतदाताओं की कमी ने पूरे अभियान को बहस के केंद्र में ला खड़ा किया है। इस विवाद के कई पहलू हैं। एक ओर निर्वाचन आयोग का तर्क है कि मृत, स्थानांतरित और अपात्र मतदाताओं के नाम हटाना सूची को विश्वसनीय बनाने के लिए जरूरी है। दूसरी ओर राजनीतिक दलों और प्रभावित नागरिकों की शिकायत है कि इस प्रक्रिया में बड़ी संख्या में वास्तविक मतदाताओं के नाम भी प्रभावित हुए हैं। कुछ स्थानों पर एक समुदाय विशेष के लोगों के नाम चुनिंदा तरीके से हटाए जाने के आरोप लगे हैं। ऐसे में सवाल केवल आंकड़ों का नहीं, बल्कि उस प्रक्रिया की विश्वसनीयता का भी है, जिसके आधार पर किसी नागरिक का मतदान का अधिकार प्रभावित हो सकता है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर ने मतदाताओं की संख्या में आई गिरावट को लेकर निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा है। उनका दावा है कि 2023 से अब तक प्रदेश में 24 लाख 99 हजार मतदाता कम हुए हैं। उन्होंने सवाल किया है कि आयोग स्पष्ट करे कि कितने नाम फॉर्म-7 के आधार पर हटाए गए और उन आवेदनों पर निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया या नहीं। अकबर ने फॉर्म-7 के इस्तेमाल की जांच कराने और गलत जानकारी देकर मतदाताओं के नाम हटवाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। उनका तर्क है कि विधानसभा चुनावों में भाजपा और कांग्रेस के बीच जीत-हार का अंतर जितना रहा, एसआईआर के दौरान उससे कई गुना अधिक नाम प्रभावित हुए हैं। इसलिए इस विषय को सामान्य प्रशासनिक कवायद मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 का भी उल्लेख किया है। इस प्रावधान के तहत मतदाता सूची में गलत जानकारी या झूठी घोषणा जानबूझकर देने पर एक वर्ष तक की कैद, जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है। अकबर का सवाल है कि आयोग ने अब तक कितनी शिकायतों को गलत पाया और ऐसे मामलों में कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की? दूसरी ओर भाजपा ने एसआईआर को लेकर कांग्रेस के आरोपों को राजनीतिक अभियान का हिस्सा बताया है। पार्टी प्रवक्ता अमित चिमनानी का कहना है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी से लेकर प्रदेश के नेता तक अपनी राजनीतिक स्थिति बचाने के लिए भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। चिमनानी ने आरोपों को चुनौती देते हुए कहा कि कांग्रेस अब तक ऐसे पर्याप्त तथ्य सामने नहीं रख सकी है, जिनसे बड़े पैमाने पर वास्तविक मतदाताओं के नाम गलत तरीके से काटे जाने की पुष्टि हो। उनका सवाल है कि यदि इतने बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है, तो प्रभावित मतदाताओं को लेकर निर्वाचन आयोग के समक्ष ठोस शिकायतें क्यों नहीं की गईं?



फॉर्म-7 के दुरुपयोग के आरोपों पर उनका कहना है कि इन प्रपत्रों की जांच की गई और जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी थी अथवा जो संबंधित पते पर नहीं रह रहे थे, उन्हीं के नाम हटाए गए। उन्होंने यह भी कहा कि फॉर्म-7 कोई भी व्यक्ति जमा कर सकता है, यदि उसे किसी मतदाता की पात्रता या निवास को लेकर संदेह हो। चिमनानी ने पलटवार करते हुए दावा किया कि कांग्रेस की ओर से भी भाजपा नेताओं के खिलाफ गलत जानकारी देकर फॉर्म-7 जमा किए गए थे। इसके चलते भाजपा से जुड़े कुछ लोगों को भी निर्वाचन कार्यालय पहुंचकर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी पड़ी। उनके मुताबिक, भाजपा ने इस प्रक्रिया का विरोध नहीं किया, बल्कि इसे निष्पक्ष सत्यापन का हिस्सा माना।

25 लाख नामों की कमी और आंकड़ों का विरोधाभास

छत्तीसगढ़ में एसआईआर के आंकड़े पहली नजर में ही कई सवाल खड़े करते हैं। पुनरीक्षण से पहले प्रदेश की मतदाता सूची में 2 करोड़ 12 लाख 30 हजार 737 मतदाता दर्ज थे। प्रारूप सूची प्रकाशित होने के बाद यह संख्या घटकर 1 करोड़ 84 लाख 95 हजार 920 रह गई। इसके बाद दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया पूरी हुई तथा अंतिम सूची में मतदाताओं की संख्या 1 करोड़ 87 लाख 30 हजार 914 दर्ज की गई। इस तरह अंतिम आंकड़ों के मुताबिक पुनरीक्षण से पहले की तुलना में प्रदेश में 24 लाख 99 हजार 823 मतदाता कम हो गए। प्रारूप सूची के मुकाबले अंतिम सूची में 2 लाख 34 हजार 994 नामों की शुद्ध बढ़ोतरी हुई। वहीं आयोग के अनुसार 1 लाख 8 हजार 807 मतदाताओं के नाम हटाए गए, जिनमें मृत और दूसरे स्थानों पर जा चुके लोग शामिल थे। इन आंकड़ों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रारूप सूची तैयार करते समय इतनी बड़ी संख्या में नाम किस आधार पर हटे और अंतिम सूची में उनमें से कितने लोगों की पात्रता की पुष्टि हुई? आबादी में वृद्धि के सामान्य रुझान के बीच मतदाताओं की संख्या में इतनी बड़ी गिरावट स्वाभाविक रूप से स्पष्टीकरण की मांग करती है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश के 33 जिलों में नाम हटाए जाने के मामले में रायपुर और कोरबा सबसे ऊपर रहे। रायपुर में 31,028, कोरबा में 15,187 और दुर्ग में 7,209 मतदाताओं के नाम हटाए गए। इसके अलावा बालोद में 3,903, बलौदाबाजार-भाटापारा में 2,662 और कबीरधाम में 2,234 नाम विलोपित किए गए। इन आंकड़ों का राजनीतिक और सामाजिक महत्व इसलिए भी है, क्योंकि रायपुर, दुर्ग और कोरबा जैसे जिलों में बड़ी संख्या में शहरी मतदाता हैं और वहां प्रवास, रोजगार तथा आवास परिवर्तन के कारण मतदाता सूची का अद्यतन जरूरी भी है। लेकिन वास्तविक रूप से स्थानांतरित और मृत मतदाताओं के नाम हटाने तथा पात्र नागरिकों के नाम गलती से हट जाने के बीच अंतर करना निर्वाचन तंत्र की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।

फॉर्म-7 बना विवाद की सबसे बड़ी वजह

छत्तीसगढ़ में एसआईआर के दौरान सबसे गंभीर विवाद फॉर्म-7 को लेकर सामने आया। यह प्रपत्र किसी मतदाता की मृत्यु अथवा संबंधित पते से स्थायी रूप से स्थानांतरित होने जैसी परिस्थितियों में उसका नाम हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आरोप है कि कुछ स्थानों पर इस प्रपत्र का इस्तेमाल वास्तविक मतदाताओं के नाम हटवाने के लिए किया गया। कई शिकायतों में दावा किया गया कि ऐसे लोगों के नाम हटाने के लिए आवेदन किए गए, जो वर्षों से अपने मूल पते पर रह रहे थे। कुछ मामलों में संबंधित मतदाताओं को निर्वाचन कार्यालय पहुंचने के बाद पता चला कि उनके नाम के विरुद्ध फॉर्म-7 जमा किया गया है। इस प्रकरण ने निर्वाचन व्यवस्था में राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों की भूमिका और शिकायतों के सत्यापन की प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े किए। नियमों के तहत नाम हटाने की शिकायत मिलने पर संबंधित मतदाता की स्थिति की जांच जरूरी है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या प्रत्येक आवेदन की पर्याप्त जांच हुई और क्या संबंधित व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का उचित अवसर मिला?

2003 की सूची बनी मतदाता की सबसे बड़ी परेशानी

एसआईआर की प्रक्रिया में 2003 की मतदाता सूची को आधार बनाए जाने से आम नागरिकों की मुश्किलें बढ़ीं। जिन लोगों का नाम पुरानी सूची में था, उन्हें उसका प्रमाण प्रस्तुत करने की जरूरत पड़ी। समस्या उन परिवारों के सामने आई, जिनके पास पुरानी सूची उपलब्ध नहीं थी या जिनके सदस्य वर्षों पहले दूसरे स्थानों पर बस गए थे। नए मतदाताओं के सामने भी अलग तरह की चुनौती थी। उनसे अपने परिजनों का 2003 की सूची में दर्ज होने का प्रमाण मांगा गया। ऐसे में पहली बार मतदान के पात्र बने युवाओं के लिए दस्तावेज जुटाना आसान नहीं रहा। निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े बूथ लेवल अधिकारियों के सामने भी मतदाताओं को नए नियम समझाने और दस्तावेज जुटवाने की चुनौती थी। ग्रामीण क्षेत्रों, दुरस्थ इलाकों और उन परिवारों के लिए परेशानी अधिक रही, जिनके पास पुराने अभिलेख सुरक्षित नहीं थे। नतीजतन आशंका जताई गई कि दस्तावेजी कठिनाइयों के कारण बड़ी संख्या में पात्र लोग भी प्रक्रिया से बाहर रह गए।

बिलासपुर से पेंड्रा तक पहुंचा विरोध

कोरबा के अलावा दूसरे इलाकों में भी इसी तरह की शिकायतें सामने आईं। बिलासपुर जिले के बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के चांटीडीह में 117 मुस्लिम मतदाताओं के नाम हटाए जाने का आरोप लगा। प्रदर्शनकारियों का दावा था कि इनमें कई परिवार दशकों से अपने पुराने पते पर रह रहे हैं। कांग्रेस नेता विजय केशरवानी के नेतृत्व में लोगों ने रैली निकालकर विरोध दर्ज कराया। गौरेला-पेंड्रा सहित अन्य क्षेत्रों में भी लोगों ने जिला निर्वाचन कार्यालय पहुंचकर शिकायतें कीं। कोरबा, बिलासपुर और पेंड्रा रोड जैसे इलाकों में हुए विरोध प्रदर्शनों ने यह स्पष्ट कर दिया कि एसआईआर का विवाद केवल राजनीतिक मंचों तक सीमित नहीं था। स्थानीय स्तर पर प्रभावित होने का दावा करने वाले लोग भी जवाब मांग रहे थे।

नागरिकता को लेकर भी पैदा हुआ भ्रम

एसआईआर के दौरान एक दूसरा संवेदनशील पहलू नागरिकता से जुड़ी आशंकाओं का रहा। राजनीतिक प्रचार में घुसपैठियों के नाम मतदाता सूची से हटाने की बात प्रमुखता से उठाई गई। इससे कुछ समुदायों के बीच यह भ्रम पैदा हुआ कि मतदाता सूची में नाम नहीं रहने पर उनकी नागरिकता भी सवालों के घेरे में आ सकती है।हालांकि मतदाता सूची में नाम दर्ज होना और किसी व्यक्ति की नागरिकता का निर्धारण दो अलग विषय हैं, लेकिन अभियान के दौरान पैदा हुई आशंकाओं ने लोगों की चिंता बढ़ाई। खासकर समुदाय विशेष के लोगों ने शिकायत की कि उनके नाम हटाए जाने की कार्रवाई ने उन्हें अनावश्यक असुरक्षा के माहौल में धकेल दिया। यहां निर्वाचन आयोग और प्रशासन की जिम्मेदारी केवल दस्तावेजों का सत्यापन करने तक सीमित नहीं रह जाती। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होता है कि किसी प्रक्रिया को लेकर नागरिकों में अनावश्यक भय न फैले।

कोरबा में उठा विवाद, प्रशासन को कराना पड़ा दोबारा सर्वे

फॉर्म-7 के कथित दुरुपयोग का सबसे चर्चित मामला कोरबा में सामने आया। एसआईआर के दौरान शहर के 1566 मतदाताओं की एक सूची सामने आई, जिनके नाम हटाए जाने का उल्लेख था। आरोप लगा कि सूची में बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाताओं के नाम शामिल थे। कुछ ईसाई और आदिवासी समुदाय के लोगों के नाम भी इसमें दर्ज बताए गए। विवाद तब और बढ़ा, जब सूची में भाजपा से जुड़े बूथ लेवल एजेंटों के नाम भी सामने आए। आरोप था कि एक ही क्षेत्र के अनेक मतदाताओं के संबंध में फॉर्म-7 जमा किए गए और उनमें से कई के बारे में यह जानकारी दी गई कि वे संबंधित पते पर निवास नहीं करते। इसके बाद मुस्लिम समाज और कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ने विरोध शुरू किया। सुन्नी मुस्लिम जमात ने भी जांच की मांग करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी। प्रशासन ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बूथ लेवल अधिकारियों से दोबारा सर्वे कराया। मुस्लिम समाज के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक में एसडीएम ने जानकारी दी कि जांच में केवल दो-तीन ऐसे मतदाता मिले, जिनकी मृत्यु हो चुकी थी। शेष लोगों के नाम सूची में यथावत होने की बात कही गई। इस घटनाक्रम ने एक महत्वपूर्ण सवाल छोड़ा कि यदि प्रारंभिक सूची में इतने नाम हटाए जाने का उल्लेख था और बाद की जांच में अधिकांश नाम सही पाए गए, तो शुरुआती सत्यापन की गुणवत्ता कैसी थी?

दोबारा नाम जुड़वाने की प्रक्रिया से बढ़ी राजनीतिक सक्रियता

देश के अलग-अलग हिस्सों में एसआईआर को लेकर विरोध और शिकायतों के बाद निर्वाचन आयोग ने नाम जोड़ने तथा छूटे हुए मतदाताओं को फिर से आवेदन का अवसर देने की प्रक्रिया शुरू की है। छत्तीसगढ़ में भी इसका राजनीतिक असर दिखाई देने लगा है। कांग्रेस के नेता प्रभावित लोगों तक पहुंचने और उनके नाम दोबारा जुड़वाने के प्रयास में जुटे हैं। दरअसल, मतदाता सूची में नामों की कटौती केवल प्रशासनिक आंकड़ों का विषय नहीं है। इसका सीधा संबंध चुनावी भागीदारी और राजनीतिक प्रतिनिधित्व से है। यदि किसी पात्र नागरिक का नाम छूट जाता है, तो वह मतदान के अधिकार से वंचित हो सकता है। दूसरी ओर, अपात्र नामों को सूची में बनाए रखना भी निष्पक्ष चुनाव की भावना के विपरीत है। इसलिए एसआईआर की सफलता का पैमाना केवल यह नहीं हो सकता कि कितने नाम हटाए गए या कितने नए नाम जोड़े गए। असली कसौटी यह होगी कि हटाए गए नामों में कितने वास्तव में अपात्र थे, कितने पात्र मतदाता गलती से बाहर हुए और शिकायतों पर कितनी निष्पक्षता से कार्रवाई की गई। छत्तीसगढ़ में करीब 25 लाख मतदाताओं की कमी, फॉर्म-7 को लेकर उठे सवाल, कोरबा जैसे जिलों में हुए विरोध और भाजपा-कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप ने निर्वाचन आयोग के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। अब जरूरत ऐसे पारदर्शी सत्यापन की है, जिसमें किसी पात्र नागरिक का नाम केवल दस्तावेजी कठिनाई, गलत शिकायत या प्रशासनिक चूक के कारण न कटे। लोकतंत्र में मतदाता सूची का शुद्धिकरण तभी सार्थक है, जब वह एक भी वास्तविक मतदाता को उसके अधिकार से वंचित किए बिना पूरा हो।



रामगोपाल अग्रवाल को हाईकोर्ट से जमानत

छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले में जेल में बंद रामगोपाल अग्रवाल को बिलासपुर हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से दर्ज शराब घोटाले के मामले में उनकी जमानत मंजूर कर ली है। जस्टिस बीडी गुरु की अदालत ने जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। हालांकि, जमानत मिलने के बावजूद अग्रवाल अभी जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। उनके खिलाफ अन्य मामलों में भी कार्रवाई चल रही है। रामगोपाल अग्रवाल ने प्रवर्तन निदेशालय के कोयला और शराब घोटाले से जुड़े मामलों के साथ ही एसीबी के चावल घोटाले के मामले में भी जमानत याचिकाएं दाखिल की हैं। इन मामलों में अभी उन्हें राहत नहीं मिली है। ऐसे में ACB के शराब घोटाले में जमानत मिलने के बाद भी उन्हें फिलहाल जेल में ही रहना होगा।



243.81 करोड़ रुपए के 18 कार्यों की निविदा मंजूर



छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में सड़कों और पुलों के 18 महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों के लिए कुल 243 करोड़ 81 लाख 11 हजार रुपए की निविदाओं को मंजूरी प्रदान की है। इनमें 12 पुल और 6 सड़क निर्माण एवं उन्नयन के कार्य शामिल हैं। राजधानी रायपुर में वीआईपी रोड के फुण्डहर चौक पर ओव्हरपास निर्माण के लिए 29 करोड़ 80 लाख 12 हजार रुपए की निविदा स्वीकृत की गई है। वहीं रिंग रोड नंबर-1 (एनएच-30) पर रायपुरा चौक फ्लाईओवर के दोनों ओर 3.66 किलोमीटर लंबी सर्विस रोड के चौड़ीकरण के लिए 14 करोड़ 96 लाख 96 हजार रुपए की निविदा मंजूर की गई है। बीजापुर जिले में कुटरू से गुटमांगी मार्ग पर इन्द्रावती नदी में उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण के लिए 36 करोड़ 5 लाख 75 हजार रुपए की निविदा मंजूर की गई है। सरगुजा जिले में दाहीडांड से सोनवरसा मार्ग पर मछली नदी में उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण के लिए 7 करोड़ 93 लाख 17 हजार रुपए की निविदा स्वीकृत की गई है।

छत्तीसगढ़ के दो कलाकारों को मिला राष्ट्रीय युवा पुरस्कार





छत्तीसगढ़ के दो प्रतिभाशाली कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी के प्रतिष्ठित उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली में 19 अक्टूबर 2026 को आयोजित समारोह में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने जशपुर के डॉ. आनन्द पाण्डेय को उत्कृष्ट अभिनय तथा सारंगढ़ के घनश्याम साहू को विशिष्ट नाट्य लेखन एवं छत्तीसगढ़ी फिल्मों में पटकथा लेखन के लिए सम्मानित किया।दोनों कलाकारों की इस उपलब्धि से छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति और रंगमंच को राष्ट्रीय स्तर पर गौरव मिला है। यह सम्मान प्रदेश के उभरते कलाकारों और रचनाकारों के लिए प्रेरणास्रोत बनेगा।

कैंसर की 137 दवाएं सस्ती



कैंसर की 137 दवाएं 9 नवंबर से सस्ती हो गई हैं। दवा कंपनियों ने 121 दवाओं के 1,364 फॉर्मूलेशन की नई कीमतें जारी की हैं। इनमें कई ब्रांड की दवाओं के दाम 50 प्रतिशत से ज्यादा घटे हैं। सबसे ज्यादा कमी 96.45 प्रतिशत तक की गई है। सरकार के अनुसार, इन दवाओं के सस्ते होने से मरीजों को हर साल करीब 3,540 करोड़ रुपये की बचत होने का अनुमान है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने कैंसर की दवाओं की कीमतों पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि 2,700 रुपये की दवा मरीज को 27,000 रुपये में मिलना दिनदहाड़े डकैती और नरसंहार जैसा है। कोर्ट ने रिटेलर कीमत और एमआरपी के बीच के भारी मार्जिन पर सवाल उठाए थे। जिसके बाद नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने 17 अक्टूबर को 137 गैर-अनुसूचित कैंसर दवाओं पर कंपनियों का मुनाफा 30 प्रतिशत तय कर दिया। इसी फैसले के बाद दवाओं की कीमतें घटी हैं।

एशियन पैरा गेम्स के पदक विजेता खिलाड़ियों का सम्मान

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एशियन पैरा गेम्स 2026 में शानदार प्रदर्शन कर देश और छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाने वाले प्रदेश के दो प्रतिभाशाली पैरा खिलाड़ियों तोमन कुमार और अभिजीत



सखूजा को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने दोनों खिलाड़ियों की उपलब्धियों की सराहना करते हुए पैरा तीरंदाजी में स्वर्ण पदक विजेता तोमन कुमार को 51 लाख रुपए और पैरा बैडमिंटन में कांस्य पदक विजेता अभिजीत सखूजा को 31 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने दोनों खिलाड़ियों को शाल एवं बस्तर कला का प्रतीक चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री एवं खेल मंत्री अरुण साव के अलावा खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव यशवंत कुमार, संचालक खेल आकांक्षा शिक्षा खलखो सहित दोनों खिलाड़ियों के परिवारजन उपस्थित थे।

दंतेवाड़ा जिला प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना में सम्मानित



कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों और किसानों की उन्नति के लिए किए जा रहे प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी पहचान मिली है। प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के अंतर्गत भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले को 'Certificate of Excellence' से सम्मानित किया गया है। इस गौरवशाली उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि, दंतेवाड़ा जिले को प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के तहत मिला यह राष्ट्रीय सम्मान छत्तीसगढ़ के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव के मार्गदर्शन में प्रशासनिक टीम, कृषि विभाग और हमारे मेहनतकश किसानों ने जिस लगन से कृषि विकास, फसल विविधीकरण और आजीविका संवर्धन के लिए कार्य किया है, उसी का परिणाम यह राष्ट्रीय मान्यता है। राज्य सरकार किसानों को सशक्त बनाने और कृषि को अधिक लाभकारी बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना और किसानों को बेहतर कृषि संसाधन उपलब्ध कराना है।

मॉडल स्कूल बनेगा महलोई का शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय



रायगढ़ जिले के महलोई स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करने की दिशा में आज भूमिपूजन किया गया। वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक ओ.पी. चौधरी ने इस अवसर पर कहा कि विद्यालय का मॉडल स्कूल के रूप में विकास विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की पहल है। मॉडल स्कूल के रूप में विकसित होने के बाद महलोई के विद्यार्थियों को आधुनिक सुविधाओं और बेहतर शिक्षा का लाभ मिलेगा। यह पहल विद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाने के साथ विद्यार्थियों को अपने सपनों और भविष्य के लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ने के अधिक अवसर प्रदान करेगी।उन्होंने शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ज्ञान और कौशल तभी सार्थक होते हैं, जब उनका उपयोग सही दिशा में किया जाए। विद्यार्थियों को नियमित अध्ययन, अनुशासन और मेहनत के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने बच्चों को अपनी रुचि और क्षमताओं को पहचानकर भविष्य निर्माण के लिए निरंतर प्रयास करने की प्रेरणा दी।

नगरनार प्लांट में एक दिन में 455 क्वाइल का उत्पादन

बस्तर के औद्योगिक नक्शे पर नगरनार स्टील प्लांट ने एक बार फिर अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। जिला मुख्यालय से 17 किलोमीटर दूर एनएमडीसी स्टील लिमिटेड की ओर से स्थापित



तीन मिलियन टन सालाना उत्पादन क्षमता के नगरनार प्लांट ने तीन नवंबर 2026 को एक ही दिन में 455 हॉट रोल्ड क्वाइल इल का उत्पादन कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। यह प्लांट की स्थापना से लेकर अब तक का एक दिन का सर्वाधिक उत्पादन है। इस उपलब्धि पर स्टील प्लांट के अधिशासी निदेशक प्रमोद कुमार सिंह ने कहा है कि 24 घंटे में 455 काइल तैयार करना हॉट स्ट्रिप मिल की तकनीकी उत्कृष्टता और कर्मचारियों की मेहनत, अनुशासन और टीम भावना का जीवंत प्रमाण है। इसी महीने की पहली तारीख को प्लांट में 440 एचआर क्वाइल का उत्पादन हुआ था, जिसे उस समय तक का सबसे बड़ा दैनिक आंकड़ा माना जा रहा था। लेकिन मात्र दो दिन के भीतर कर्मचारियों ने अपना ही रिकार्ड तोड़कर साबित कर दिया। एनएमडीसी स्टील लिमिटेड के महाप्रबंधक एवं संचार प्रमुख रफीक अहमद जिनाबड़े ने स्टील उत्पादन की जानकारी साझा करते हुए कहा कि यह सफलता अचानक नहीं मिली है। वर्ष 2025-26 में नगरनार स्टील प्लांट ने कुल 23,24,902 टन का उत्पादन किया था, जो पिछले वर्ष के 14,38,646 टन के मुकाबले करीब 63 प्रतिशत अधिक है। इस तेज रफ्तार ने ही आज के रिकार्ड की नींव रखी है।

हर संभाग में होगा एफटीए जागरूकता कार्यशाला

छत्तीसगढ़ सरकार निर्यातकों को भारत के मुक्त व्यापार समझौतों का अधिकतम लाभ दिलाने के लिए प्रदेश में एक समर्पित FTA एक्सेलरेटर, FTA हेल्पडेस्क और हिंदी-अंग्रेजी में द्विभाषी FTA गाइडबुक स्थापित करेगी। इसके साथ ही प्रदेश के प्रत्येक संभाग में FTA जागरूकता कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने इसकी घोषणा की। वे रायपुर में विदेश



व्यापार महानिदेशालय, भारत सरकार के वाणिज्य विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। कार्यशाला में छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 300 निर्यातकों के साथ भारत सरकार एवं राज्य सरकार के अधिकारियों तथा निर्यात संवर्धन परिषदों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यशाला का उद्देश्य भारत द्वारा हाल ही में किए गए मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) से खुलने वाले नए अवसरों के प्रति निर्यातकों को जागरूक करना तथा विभिन्न उत्पादों के लिए क्षेत्रवार रणनीति तैयार कर इन समझौतों का अधिकतम लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करना था।

अम्बेडकर अस्पताल में जटिल कैंसर सर्जरी सफल

छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय में चिकित्सकों ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। यहां कैंसर सर्जरी विभाग की टीम ने हृदय और फेफड़े की प्रमुख संरचनाओं से चिपकी कैंसर की जटिल गांठ को सफलतापूर्वक निकाल दिया। 60 वर्षीय मरीज की यह सर्जरी करीब चार घंटे चली। ऑपरेशन के बाद मरीज की हालत स्थिर



रही और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। अब वे पूरी तरह स्वस्थ हैं और सामान्य जीवन जी रहे हैं। रायपुर निवासी इस मरीज को छाती में दर्द और भारीपन की शिकायत थी। वह कैंसर सर्जरी विभाग की ओपीडी में पहुंचा। इससे पहले निजी अस्पताल में बायोप्सी कराने पर इनवेसिव थाइमोमा (कैंसर) की पुष्टि हो चुकी थी। मरीज कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी भी करवा चुका था। कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन में छाती के अगले हिस्से में करीब 5 × 4.3 × 2.5 सेंटीमीटर की गांठ मिली। यह गांठ हृदय की प्रमुख रक्त वाहिकाओं (महाधमनी और पल्मोनरी आर्टरी), बाएं फेफड़े और हृदय की झिल्ली से चिपकी हुई थी। गांठ की संवेदनशील स्थिति को देखते हुए कैंसर सर्जरी विभागाध्यक्ष डॉ. आशुतोष गुप्ता ने हार्ट, चेस्ट एंड वैस्कुलर सर्जरी विभागाध्यक्ष डॉ. के. के. साहू से सलाह ली। दोनों विभागों की टीम ने मिलकर सर्जरी का फैसला किया। ऑपरेशन में छाती के मध्य भाग में चीरा लगाकर मीडियन स्टर्नोटॉमी तकनीक से गांठ तक पहुंचा गया। चिकित्सकों ने बहुत सावधानी से गांठ को हृदय की झिल्ली के एक हिस्से और बाएं फेफड़े के कुछ हिस्से के साथ निकाल दिया। सर्जरी के दौरान मरीज को दो यूनिट रक्त चढ़ाया गया। कोई बड़ी जटिलता नहीं हुई। इस सफल सर्जरी में डॉ. आशुतोष गुप्ता और डॉ. के. के. साहू के नेतृत्व में डॉ. किशन सोनी, डॉ. गुंजन अग्रवाल, डॉ. सोनम, डॉ. समृद्ध, डॉ. लावण्या, डॉ. आशीष मालव, डॉ. गौरव और डॉ. अक्षय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। निश्चेतना विशेषज्ञ डॉ. संकल्प भी टीम में शामिल रहे। चिकित्सा अधीक्षक डॉ. संतोष सोनकर ने कहा कि अम्बेडकर अस्पताल में मरीजों को बेहतर और उन्नत इलाज उपलब्ध कराने के प्रयास लगातार जारी हैं। इस जटिल ऑपरेशन में दोनों विभागों के डॉक्टरों के टीम वर्क और विशेषज्ञता से मरीज की जान बचाई गई।

766 करोड़ के निवेश का खुलेगा राज!

महादेव ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर से पूछताछ पर टिकी जांच एजेंसियों की निगाहें

अमेरिकी कंपनी के अधिग्रहण से लेकर दुबई के ठिकानों तक फैली है पैसों की कहानी

महादेव ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क के प्रमुख संचालक सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी ने हजारों करोड़ रुपये के कथित अवैध कारोबार की जांच को एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया है। अब तक इस मामले में सामने आए बैंक खातों, हवाला कारोबार, विदेशी निवेश और कंपनियों के अधिग्रहण की कड़ियों को जोड़ने के लिए जांच एजेंसियों को उसके बयानों से अहम सुराग मिलने की उम्मीद है। करीब तीन साल तक देश से बाहर रहने के बाद ओमान से भारत लाए गए सौरभ से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की पूछताछ का केंद्र केवल सट्टे के कारोबार का संचालन नहीं, बल्कि उससे पैदा हुई रकम का अंतिम ठिकाना भी है। इस प्रकरण में सबसे बड़ा सवाल करीब 765.77 करोड़ रुपये का है। ईडी का आरोप है कि महादेव सट्टा नेटवर्क से हासिल कथित अवैध धन का इस्तेमाल अमेरिकी कंपनी एबिक्स इंक के अधिग्रहण में किया गया। यह रकम अलग-अलग वित्तीय माध्यमों से कारोबारी विकास गर्ग से जुड़ी कंपनियों तक पहुंचाई गई। यदि जांच एजेंसी के आरोप प्रमाणित होते हैं, तो यह मामला ऑनलाइन सट्टेबाजी से आगे बढ़कर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धन के स्रोत को छिपाने और उसे वैध कारोबारी पूंजी के रूप में स्थापित करने की कथित सुनियोजित कोशिश का उदाहरण बन सकता है। 13 नवंबर को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तारी के बाद रायपुर की विशेष अदालत ने सौरभ को सात दिन की ईडी रिमांड पर सौंपा है। 19 नवंबर तक चलने वाली पूछताछ में एजेंसी के सामने डिजिटल साक्ष्यों, वित्तीय दस्तावेजों, सहयोगियों के बयानों और विदेशी कंपनियों से जुड़े रिकॉर्ड का मिलान करने की चुनौती है। जांच की दिशा अब इस बात पर केंद्रित है कि सट्टे से जुटाई गई रकम किन-किन रास्तों से गुजरी और आखिरकार उसका लाभ किसे मिला।



766 करोड़ का निवेश, अमेरिकी कंपनी तक कैसे पहुंची रकम

महादेव प्रकरण की जांच में सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय कड़ी अमेरिकी सॉफ्टवेयर कंपनी एबिक्स इंक के अधिग्रहण से जुड़ी है। ईडी ने अपनी पड़ताल में विकास गर्ग और उनसे संबंधित कारोबारी संस्थाओं को इस लेन-देन का अहम हिस्सा बताया है। एजेंसी के मुताबिक, सट्टेबाजी से अर्जित करीब 765.77 करोड़ रुपये विभिन्न वित्तीय माध्यमों से इन कंपनियों तक पहुंचाए गए। इस प्रक्रिया में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट जैसे रास्तों का इस्तेमाल किए जाने का आरोप है। जांच एजेंसी का दावा है कि इस रकम का उपयोग एबिक्स इंक में हिस्सेदारी खरीदने के लिए किया गया। एराया लाइफस्पेसेज से जुड़ी कंपनियों ने अगस्त 2024 में अमेरिकी दिवालियापन अदालत की प्रक्रिया के माध्यम से एबिक्स में 97.58 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल की थी। इस अधिग्रहण का कुल मूल्य लगभग 1,175 करोड़ रुपये बताया गया है। इसमें ईडी द्वारा संदिग्ध मानी गई 765.77 करोड़ रुपये की रकम को पूरे सौदे की राशि से अलग समझना जरूरी है। इस मामले में एजेंसी ने विकास गर्ग, उसके परिजनों और उनसे संबंधित कंपनियों की लगभग 940.77 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच की हैं। इनमें एबिक्स से जुड़ी हिस्सेदारी भी शामिल है। जांच का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि क्या सट्टे से अर्जित धन को कई कंपनियों और निवेश माध्यमों से गुजारकर उसकी पहचान बदलने की कोशिश की गई थी। सौरभ से पूछताछ में यह जानने का प्रयास होगा कि इस निवेश की योजना किसने बनाई, रकम उपलब्ध कराने वाले कौन थे और अधिग्रहण के बाद वास्तविक आर्थिक लाभ किन लोगों को मिला।

दुबई से संचालित नेटवर्क, भारत में फैला सट्टे का जाल

जांच एजेंसियों के अनुसार, सौरभ चंद्राकर और उसके सहयोगी रवि उप्पल ने महादेव ऑनलाइन बुक के नाम से सट्टेबाजी का ऐसा ढांचा तैयार किया था, जिसका संचालन विदेश में बैठकर किया जाता था, लेकिन ग्राहकों और पैसों का बड़ा हिस्सा भारत से जुड़ा था। क्रिकेट, फुटबॉल, ताश और अन्य खेलों पर दांव लगाने के लिए अलग-अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाए गए थे। देश के विभिन्न हिस्सों में पैनल संचालकों और स्थानीय नेटवर्क के माध्यम से ग्राहकों को जोड़ा जाता था। इस व्यवस्था की खासियत इसका बहुस्तरीय संचालन था। मुख्य संचालकों का नियंत्रण विदेश से रहता था, जबकि स्थानीय स्तर पर पैनल चलाने वाले लोग ग्राहकों से रकम जुटाते थे। इस तरह कारोबार के अलग-अलग हिस्सों को अलग-अलग व्यक्तियों के माध्यम से संचालित किया जाता था। जांच एजेंसियों का आरोप है कि इससे वास्तविक संचालकों तक पहुंचना और धन के मूल स्रोत की पहचान करना मुश्किल हो जाता था। ईडी की जांच में सामने आया कि सट्टे से प्राप्त रकम को सीधे मुख्य संचालकों तक पहुंचाने के बजाय दूसरे लोगों के नाम पर खोले गए बैंक खातों का इस्तेमाल किया जाता था। इन खातों से कई स्तरों पर लेन-देन के बाद रकम हवाला के जरिए विदेश भेजी जाती थी। एजेंसी ने इस नेटवर्क से हर महीने 450 करोड़ रुपये से अधिक की कथित अपराध आय पैदा होने का अनुमान लगाया है। कुछ हालिया जांच संबंधी आकलनों में 2019 से अब तक करीब 80 हजार करोड़ रुपये के कारोबार या कथित अवैध कमाई का उल्लेख भी सामने आया है। हालांकि इन आंकड़ों का अंतिम निर्धारण जांच और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर ही हो सकेगा।



हजारों करोड़ की संपत्तियों पर कार्रवाई

महादेव सट्टा प्रकरण की व्यापकता का अंदाजा ईडी की अब तक की कार्रवाई से लगाया जा सकता है। देशभर में करीब 190 ठिकानों पर तलाशी ली जा चुकी है। एजेंसी की अलग-अलग कार्रवाइयों में लगभग 2,000 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त या फ्रीज की गई हैं, जबकि करीब 3,500 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच की गई हैं। इनमें लगभग 1,800 करोड़ रुपये की विदेश स्थित संपत्तियां शामिल बताई गई हैं। दुबई में मौजूद 22 अचल संपत्तियों पर भी कार्रवाई की गई है। ईडी इस मामले में अब तक 116 आरोपियों के खिलाफ छह अभियोजन शिकायतें दाखिल कर चुकी है। सौरभ चंद्राकर इस प्रकरण में गिरफ्तार होने वाला 15वां व्यक्ति है। जांच के दौरान एजेंसी ने केवल सट्टेबाजी के स्थानीय पैनल तक अपनी पड़ताल सीमित नहीं रखी, बल्कि दुबई स्थित मुख्य संचालन केंद्र, हवाला कारोबारियों और शेयर बाजार में निवेश करने वाले लोगों तक वित्तीय लेन-देन का पता लगाने की कोशिश की। सितंबर 2023 में दुबई की कंपनियों के पास मौजूद लगभग 236 करोड़ रुपये की प्रतिभूतियों को फ्रीज करने की कार्रवाई भी इसी जांच का हिस्सा थी। वहीं, जुलाई 2026 में विकास गर्ग की गिरफ्तारी के बाद अमेरिकी कंपनी के अधिग्रहण से जुड़ा वित्तीय पहलू अधिक स्पष्ट होकर सामने आया। ईडी के अनुसार, गर्ग से जुड़ी कंपनियों तक सट्टेबाजी से अर्जित करीब 940 करोड़ रुपये पहुंचे थे। इनमें से लगभग 766 करोड़ रुपये एबिक्स के अधिग्रहण में लगाए जाने का आरोप है। अलग-अलग समय पर हुई जब्ती, संपत्ति अटैच करने और रकम फ्रीज करने की कार्रवाइयों के आंकड़ों को एक ही श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। फिर भी इनसे यह स्पष्ट होता है कि जांच का दायरा केवल एक ऑनलाइन ऐप या उसके संचालकों तक सीमित नहीं है। एजेंसी अब इस पूरे वित्तीय ढांचे की परतें खोलने में जुटी है।

गिरफ्तारी से आगे, असली चुनौती पैसों का अंतिम हिसाब

महादेव ऐप प्रकरण अब केवल ऑनलाइन सट्टेबाजी के कारोबार और उसके प्रमुख संचालकों की गिरफ्तारी का मामला नहीं रह गया है। इसकी परिधि में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय लेन-देन, हवाला, विदेशी कंपनियों में निवेश, संपत्तियों की खरीद और कथित भ्रष्टाचार जैसे गंभीर पहलू शामिल हो चुके हैं। सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी इस पूरे नेटवर्क की जांच में महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, लेकिन इससे मामले का निष्कर्ष अपने आप सामने नहीं आ जाएगा। करीब 766 करोड़ रुपये का कथित निवेश इस प्रकरण की सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय कड़ियों में से एक है। यदि ईडी यह प्रमाणित कर पाती है कि सट्टे से अर्जित धन को सुनियोजित तरीके से विदेशी कंपनियों और निवेश माध्यमों के जरिए अमेरिकी कंपनी के अधिग्रहण तक पहुंचाया गया, तो यह मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बड़ी सफलता होगी। हालांकि जांच की वास्तविक सफलता केवल बड़े आंकड़े सामने लाने या आरोपियों से पूछताछ करने में नहीं होगी। जरूरी यह है कि प्रत्येक वित्तीय लेन-देन का दस्तावेजी प्रमाण जुटाया जाए और अपराध से अर्जित रकम का स्रोत, उसके हस्तांतरण की प्रक्रिया तथा अंतिम लाभार्थियों की पहचान स्थापित की जाए। सौरभ के पास इस पूरे नेटवर्क के संचालन, उसके सहयोगियों और वित्तीय व्यवस्था से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां होने की संभावना है। अब देखना यह होगा कि उसकी पूछताछ से जांच एजेंसियां कितनी कड़ियां जोड़ पाती हैं। सट्टे के कारोबार से निकली रकम अमेरिकी कंपनी तक कैसे पहुंची, इसके पीछे कौन-कौन से चेहरे थे और इस पूरी व्यवस्था का वास्तविक लाभ किसने उठाया, इन सवालों का जवाब ही महादेव प्रकरण की जांच को निर्णायक मुकाम तक पहुंचाएगा।

200 करोड़ की शादी ने भी खोले खर्च के रास्ते

सौरभ चंद्राकर की फरवरी 2023 में संयुक्त अरब अमीरात के रास अल खैमाह में हुई भव्य शादी भी इस पूरे प्रकरण की जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ईडी के अनुसार, इस आयोजन पर करीब 200 करोड़ रुपये नकद खर्च किए गए थे। मेहमानों को भारत से आयोजन स्थल तक पहुंचाने के लिए नागपुर से तीन चार्टर्ड विमान भेजे जाने की जानकारी भी जांच में सामने आई थी। एजेंसी ने इस आयोजन से जुड़ी इवेंट कंपनियों, होटल संचालकों और अगड़िया फर्मों के वित्तीय लेन-देन की पड़ताल की है। इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि इतनी बड़ी रकम किस स्रोत से जुटाई गई और भुगतान किन लोगों के माध्यम से किया गया। आयोजन में शामिल लोगों और सेवाएं उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं की भूमिका भी जांच के दायरे में रही है। इस शादी का महत्व केवल इसकी भव्यता तक सीमित नहीं है। जांच एजेंसी यह समझना चाहती है कि सट्टे के कारोबार से जुड़े लोगों ने अपनी आर्थिक हैसियत और खर्च की क्षमता किस तरह विकसित की। किसी महंगे आयोजन को अपने आप में अपराध का प्रमाण नहीं माना जा सकता, लेकिन जब खर्च का पैमाना और आय का घोषित स्रोत मेल न खाएं, तो वित्तीय जांच जरूरी हो जाती है।

ओमान से भारत तक पहुंचने में लगा लंबा वक्त

सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी तक पहुंचने के लिए भारतीय एजेंसियों को लंबी अंतरराष्ट्रीय कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। जांच में सहयोग के लिए जारी समन पर पेश नहीं होने के बाद उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया। इसके बाद इंटरपोल की ओर से रेड नोटिस जारी हुआ। उसकी नागरिकता और विदेशी यात्रा दस्तावेजों से जुड़ी जानकारियां भी जांच का हिस्सा बनीं। ओमान की अदालत ने 8 अक्टूबर 2026 को उसके प्रत्यर्पण की अनुमति दी। इसके बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो की टीम उसे 1 नवंबर को भारत लेकर आई। एजेंसी के अनुसार, मस्कट हवाई अड्डे से फर्जी यात्रा दस्तावेजों के सहारे बाहर जाने की कोशिश के दौरान उसे पकड़ा गया था। भारत पहुंचने के बाद सीबीआई ने उससे पूछताछ की। आठ दिन की हिरासत अवधि पूरी होने पर 12 नवंबर को विशेष सीबीआई अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अलग से गिरफ्तारी की अनुमति लेकर उसे अपनी हिरासत में लिया। अब दोनों जांच एजेंसियों की पड़ताल के अलग-अलग पहलुओं को समझना भी जरूरी है। सीबीआई कथित सट्टेबाजी नेटवर्क और उससे जुड़े अपराधों की जांच कर रही है, जबकि ईडी का प्रमुख फोकस अपराध से अर्जित धन, उसके हस्तांतरण और निवेश के तरीकों पर है। सौरभ के बयान इन दोनों जांचों के बीच कई महत्वपूर्ण कड़ियां जोड़ सकते हैं।

अटल के सपने से विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प तक

मोदी के मार्गदर्शन और साय के सुशासन में विकास की नई उड़ान



विरासत के संरक्षण के साथ कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य और अधोसंरचना को मिली नई गति

छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा में तीन महत्वपूर्ण पड़ाव एक-दूसरे से जुड़े दिखाई देते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूरदृष्टि ने अलग राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ के निर्माण का सपना साकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का लक्ष्य सामने रखकर राज्यों को विकास की नई दिशा और गति देने का संकल्प लिया। वहीं मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए सुशासन, जनकल्याण और निवेश को केंद्र में रखकर आगे बढ़ रही है।

अटल की कल्पना, मोदी के संकल्प और साय के नेतृत्व का यह समन्वय प्रदेश को वर्ष 2047 तक विकसित और आत्मनिर्भर राज्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण आधार तैयार कर रहा है। एक नवंबर 2000 को मध्यप्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ देश के 26वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। शुरुआती दौर में सीमित वित्तीय संसाधन, प्रशासनिक चुनौतियां और आधारभूत सुविधाओं की कमी बड़ी बाधा थीं। करीब सात से आठ हजार करोड़ रुपये के शुरुआती बजट वाला राज्य अब लगभग 1.72 लाख करोड़ रुपये के बजट तक पहुंच चुका है। यह बदलाव प्रदेश की बढ़ती आर्थिक क्षमता और विकास की विस्तृत होती संभावनाओं को दर्शाता है। बीते 26 वर्षों में कृषि, उद्योग, सड़क, रेल, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के क्षेत्रों में हुए विस्तार ने छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदली है।

किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था विकास की धुरी

धान का कटोरा कहलाने वाले छत्तीसगढ़ में किसानों की समृद्धि को विकास का प्रमुख आधार बनाया गया है। विष्णु देव साय सरकार ने किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने के लिए 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की व्यवस्था की है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में 25.24 लाख किसानों से 141.04 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन किया गया। समर्थन मूल्य और कृषक उन्नति योजना को मिलाकर किसानों को करीब 43,723 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। बीते तीन खरीफ सीजन में लगभग 437 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी और किसानों को 1.40 लाख करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व को रेखांकित करता है। ऑनलाइन टोकन, बायोमेट्रिक सत्यापन और डिजिटल निगरानी से खरीदी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने का प्रयास हुआ है। कृषि यंत्रों, फार्म मशीनरी बैंकों और ड्रिप-स्प्रिंकलर सिंचाई के विस्तार से खेती को आधुनिक बनाने की दिशा में भी काम हो रहा है।

महिला सशक्तिकरण और आवास से सामाजिक सुरक्षा

विकास का अर्थ तभी व्यापक होता है, जब उसका लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। महतारी वंदन योजना के माध्यम से लगभग 68 लाख पात्र महिलाओं को 31 किस्तों में 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे बैंक खातों में दी जा चुकी है। प्रदेश में 13.85 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं और बिहान मिशन के माध्यम से 31 लाख से अधिक गरीब परिवारों की महिलाएं स्व-सहायता समूहों से जुड़ी हैं। इन प्रयासों से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और आत्मनिर्भरता को मजबूती मिली है। आवास के क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाखों परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराने का काम आगे बढ़ा है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आवास निर्माण से उन परिवारों को सुरक्षा और सम्मान का आधार मिल रहा है, जो लंबे समय तक कच्चे और जर्जर मकानों में रहने को मजबूर थे। आवास के साथ बिजली, पेयजल, शौचालय, रसोई गैस और राशन जैसी सुविधाएं जुड़ने से जीवन स्तर में व्यापक सुधार की संभावनाएं बनी हैं।

उद्योग, निवेश और रोजगार के नए अवसर

छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा, ऊर्जा क्षमता और कृषि उत्पादन प्रदेश की औद्योगिक ताकत हैं। कोयला, लौह अयस्क और बॉक्साइट जैसे संसाधनों के साथ इस्पात, सीमेंट और ऊर्जा उत्पादन ने राज्य को देश के औद्योगिक नक्शे पर मजबूत पहचान दी है। नई औद्योगिक नीति 2024-30 के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, टेक्सटाइल और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रदेश में 450 से अधिक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार लागू किए गए हैं। नई औद्योगिक नीति के बाद आठ लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिलने का दावा है, जिनसे 1.72 लाख से अधिक संभावित रोजगार अवसरों का रास्ता खुल सकता है। सिंगल विंडो व्यवस्था, सरल प्रक्रियाएं और जन विश्वास सुधार निवेश के लिए अनुकूल वातावरण बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। चुनौती यह होगी कि निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतरें और स्थानीय युवाओं को कौशल के अनुरूप रोजगार मिले।

सड़क, रेल और डिजिटल कनेक्टिविटी से सिमटती दूरियां

प्रदेश के विकास में आधारभूत ढांचे का विस्तार निर्णायक भूमिका निभा रहा है। ग्रामीण सड़कों के विस्तार से दूरस्थ गांवों का जिला मुख्यालयों और शहरों से संपर्क बेहतर हुआ है। रायपुर-विशाखापट्टनम और रायपुर-धनबाद आर्थिक गलियारों जैसी परियोजनाएं व्यापार, परिवहन और औद्योगिक गतिविधियों को नई गति देने की क्षमता रखती हैं। रेल नेटवर्क के विस्तार पर भी बड़ा निवेश हो रहा है। प्रदेश में करीब 51 हजार करोड़ रुपये की रेल परियोजनाओं पर काम जारी है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए रेलवे बजट आवंटन बढ़कर 7,470 करोड़ रुपये हो गया है। दल्लीराजहरा-रावघाट रेल लाइन का विस्तार और बस्तर को रेल नेटवर्क से जोड़ने की पहल क्षेत्रीय विकास के लिहाज से महत्वपूर्ण है। सड़क, रेल और मोबाइल नेटवर्क का विस्तार दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और रोजगार तक पहुंच आसान बना सकता है।

स्वास्थ्य, शिक्षा और सुशासन से मजबूत होता विश्वास

स्वस्थ और शिक्षित समाज के बिना विकसित राज्य की कल्पना अधूरी है। प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों का विस्तार हुआ है। नवा रायपुर में पांच हजार बिस्तरों की क्षमता वाले मेडिसिटी हब की योजना और मेकाहारा में अस्पताल सुविधाओं के विस्तार से स्वास्थ्य सेवाओं को नई क्षमता मिलने की उम्मीद है। आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और एम्स जैसे संस्थानों की मौजूदगी ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश की स्थिति मजबूत की है। हालांकि स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता पर निरंतर ध्यान देना होगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सुशासन को नागरिकों के अनुभव से जोड़ने पर जोर है। सेवा सेतु के माध्यम से 38 विभागों की 939 सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। 16 हजार से अधिक सेवा केंद्रों के नेटवर्क और लाखों ऑनलाइन आवेदनों से प्रशासनिक सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने का प्रयास हुआ है। जनसमस्या निवारण शिविर, सुशासन सेवा संवाद और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन जैसी पहलें शासन और जनता के बीच दूरी कम करने का माध्यम बन सकती हैं। इनकी वास्तविक सफलता समयबद्ध समाधान, पारदर्शिता और नागरिकों के साथ संवेदनशील व्यवहार से तय होगी।

बस्तर में सुरक्षा के साथ विकास और जनजातीय विरासत का सम्मान

छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा में बस्तर और सरगुजा के दूरस्थ अंचलों को मुख्यधारा से जोड़ना विशेष महत्व रखता है। नक्सलवाद के विरुद्ध सुरक्षा अभियानों के साथ सड़क, पुल, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी और संचार सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। बस्तर की 485 बसाहटों को मुख्य मार्गों से जोड़ने की स्वीकृति और अन्य 280 बसाहटों के लिए सड़क प्रस्ताव इस दिशा में महत्वपूर्ण पहल हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा जैसी योजनाएं भी दूरस्थ गांवों में आवागमन की सुविधा बढ़ा रही हैं। विकास की इस प्रक्रिया में जनजातीय संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण भी उतना ही जरूरी है। नवा रायपुर में निर्मित शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक सह आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय इसी सोच का उदाहरण है। यहां जनजातीय जीवन, पारंपरिक कृषि, लोककला, वाद्ययंत्रों और ऐतिहासिक आंदोलनों को आधुनिक तकनीक के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। बस्तर का घोटुल, पारंपरिक चिकित्सा, हस्तशिल्प और लोकनृत्य प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम बन रहे हैं।



2047 का लक्ष्य: विरासत, विकास और विश्वास का समन्वय

छत्तीसगढ़ की पहचान उसकी प्राकृतिक संपदा, जनजातीय संस्कृति, लोक परंपराओं और मेहनतकश समाज से है। विकास की गति के साथ इस विरासत को सुरक्षित रखना भी उतना ही आवश्यक है। पर्यटन स्थलों का विकास, स्थानीय कलाकारों और शिल्पकारों को प्रोत्साहन तथा धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों का संरक्षण प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नए अवसर दे सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस छत्तीसगढ़ की कल्पना को राज्य का स्वरूप दिया, वह अब विकसित भारत के व्यापक लक्ष्य के साथ अपनी नई पहचान गढ़ रहा है। नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित राष्ट्र के संकल्प और विष्णु देव साय के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 का उद्देश्य प्रदेश को आत्मनिर्भर, समृद्ध और अवसरों से भरपूर बनाना है। इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किसानों की आय में स्थायी वृद्धि, युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य की बेहतर पहुंच तथा जनजातीय क्षेत्रों का संतुलित विकास जरूरी होगा। योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और नागरिकों का शासन पर भरोसा मजबूत हो, यही विकास की असली कसौटी है। अटल की दूरदृष्टि से शुरू हुई राज्य निर्माण की यात्रा, मोदी के विकसित भारत के संकल्प और साय के सुशासन के साथ विरासत, विकास और विश्वास के नए सोपान तय कर सकती है।

हल्के में न लें ये लक्षण

बड़ी बीमारी के संकेत होते हैं कई बार छोटे-छोटे लक्षण

क्या आपको पता है कि किसी भी गंभीर बीमारी की शुरुआत एक छोटे से लक्षणों से होती है. कभी-कभी मामूली दिखने वाले लक्षण किसी गंभीर बीमारी का संकेत देते हैं. इसलिए लंबे समय तक कोई परेशानी होने पर उसे टालना नहीं चाहिए. किसी भी गंभीर बीमारी की शुरुआत एक हल्के लक्षणों के साथ होती है. यह लक्षण इतने मामूली होते हैं कि हम उन पर ध्यान नहीं देते. हालांकि यह कोई बड़ी बीमारी का संकेत भी होता है. शरीर में होने वाले इन लक्षणों को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए. आइए जानें वो कौन से लक्षण हैं जिन्हें हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए और उसके लिए क्या करें.

जोड़ों में दर्द

जोड़ों में दर्द गंभीर बीमारी के संकेत देते हैं. अगर आपकी उम्र 20 से 30 साल के बीच है और आपको चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो इसका मतलब कैल्शियम की कमी हो गई है. अब तो युवा पीढ़ी तेजी से इसकी चपेट में आ रही है. कारण है फास्ट फूड का सेवन ज्यादा करना. तो इसको भी इग्नोर ना करें डॉक्टर को दिखाएं. जोड़ों में सूजन या दर्द इन्फ्लेमेशन डिजीज का संकेत हो सकता है. अगर आपको लंबे समय तक आपके जोड़ों में दर्द है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं.





सिर दर्द

अगर आपके सिर में रोजाना दर्द बना रहता है तो इसका मतलब आपको माइग्रेन की परेशानी हो गई है. आपको इसकी जांच तुरंत डॉक्टर से करा लेनी चाहिए. यह परेशानी वैसे नींद न पूरी होने और तनाव के कारण हो सकती है.



सीने में दर्द

अगर आपके सीने में कभी दर्द महसूस हो तो बिना देरी किए डॉक्टर को दिखाएं. इस दर्द को तो बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. यह हार्ट अटैक का वार्निंग साइन है.

मांसपेशियों में दर्द

अगर आपको चलने फिरने में परेशानी होने लगी है तो मतलब विटामिन डी (vitamin d) कम हो गई है. ऐसे में आप सबसे पहले तो अपने आहार में बदलाव करें और जाकर हेल्थ चेकअप भी करवाएं.

अचानक वजन कम

मोटे लोगों का जब वजन कम होता है तो वे खुश होते हैं, लेकिन अचानक वजन कम हुआ तो ये गंभीर बात होती है. अगर बिना कुछ किए आपका वजन अचानक कम होने लगे तो समझ जाइए कि ये कोई गंभीर बीमारी का संकेत है. अगर कुछ महीने में 10 फीसदी से ज्यादा वजन कम हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें.

बुखार

लगातार हल्का बुखार बने रहना सेहत के लिए अच्छा नहीं है. हल्का बुखार आपको शरीर में संक्रमण का संकेत देता है. अगर बुखार के साथ जोड़ों में दर्द है या कोई दिक्कत है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं.

मूड स्विंग

अगर छोटी छोटी बात पर बिना कारण के आपका मूड स्विंग हो जाता और ये बार-बार हो रहा है, इसके कारण आप चिड़चिड़े स्वभाव के होते जा रहे हैं, तो इसे हल्के में न लें. ये गंभीर मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं जैसे कि बाइपोलर विकार, डायस्टीमिया का संकेत हो सकता है. ऐसे में आपको विशेषज्ञ से परामर्श करना चाहिए.

चिड़चिड़ापन

खराब मूड या तनाव से अक्सर चिड़चिड़ापन रहता है. अगर आप ज्यादा चिड़चिड़े हैं तो ये दिमाग से जुड़ी किसी बीमारी का संकेत हो सकता है.

चोट

अगर शरीर में कहीं भी चोट लगी हो और उसको ठीक होने में टाइम लगता है तो ये डायबिटीज का संकेत हो सकता है. अगर आपको कुछ महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं.

थकान

पूरी नींद के बाद भी आपको थकान महसूस होती है तो ये क्रोनिक फटीग सिंड्रोम या किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है.

खांसी

लगातार खांसी की समस्या होना, खांसी के साथ वजन कम होना, हल्का बुखार आदि होने पर विशेषज्ञ से परामर्श करना चाहिए. ये छाती का संक्रमण हो सकता है. इसके अलावा भी किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है.

भव्यता का महाकाव्य

'रामायण' ने बॉक्स ऑफिस पर रचा इतिहास, महाकाव्य को वैश्विक सिनेमाई अनुभव बनाने की कोशिश



नितेश तिवारी की 'रामायण: पार्ट वन' ने रिलीज के पहले आठ दिनों में ही दुनिया भर से 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई कर भारतीय सिनेमा के बड़े व्यावसायिक पड़ाव को छू लिया है। रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश अभिनीत इस फिल्म की सफलता का पैमाना असाधारण है, लेकिन इसकी चर्चा केवल कमाई तक सीमित नहीं है। फिल्म ने तकनीकी भव्यता, अंतरराष्ट्रीय प्रस्तुति और कलाकारों के अभिनय से दर्शकों का ध्यान खींचा है, वहीं इसकी पटकथा, भावनात्मक गहराई और रामकथा की मूल संवेदना को लेकर सवाल भी उठे हैं। यही विरोधाभास इसे एक दिलचस्प सिनेमाई घटना बनाता है।

5 नवंबर को सिनेमाघरों में पहुंची फिल्म ने आठ दिनों में दुनिया भर से अनुमानित 1,033.55 करोड़ रुपये का ग्रॉस कारोबार किया। इसमें भारत का ग्रॉस कलेक्शन 675.05 करोड़ और विदेशी बाजारों का योगदान 358.50 करोड़ रुपये बताया गया है। इस उपलब्धि के साथ फिल्म 1,000 करोड़ क्लब में पहुंचने वाली 11वीं भारतीय फिल्म और यह मुकाम सबसे तेजी से हासिल करने वाली तीसरी भारतीय फिल्म बनी। इससे आगे 'पुष्पा 2' और 'धुरंधर 2' हैं, जिन्होंने सात दिनों में यह आंकड़ा छुआ था। आंकड़े का अंतर भी ध्यान देने योग्य है। सातवें दिन यानी बुधवार को भारत में फिल्म का नेट कलेक्शन 61.10 करोड़ नहीं, बल्कि उपलब्ध ट्रेड रिपोर्टों के अनुसार करीब 70.65 करोड़ रुपये था। आठवें दिन इसकी कमाई घटकर 53.50 करोड़ रुपये रही। इसलिए लगातार सात दिन 100 करोड़ रुपये से अधिक की वैश्विक कमाई का सिलसिला आठवें दिन टूट गया। आठ दिनों का भारत नेट कलेक्शन 564.60 करोड़ रुपये बताया गया है, जिसके आधार पर फिल्म ने 'पठान' और 'एनिमल' के घरेलू लाइफटाइम नेट कलेक्शन को पीछे छोड़ा। करीब चार हजार करोड़ रुपये के बताए जा रहे दोनों भागों के बजट के साथ बनी यह परियोजना भारतीय सिनेमा के सबसे महत्वाकांक्षी प्रयासों में गिनी जा रही है। फिल्म का लगभग 195 मिनट का पहला भाग कथा को केवल धार्मिक आख्यान के रूप में नहीं, बल्कि एक बड़े फैंटेसी एडवेंचर और एक्शन ड्रामा के रूप में प्रस्तुत करता है। निर्माता नमित मल्होत्रा ने अंतरराष्ट्रीय तकनीकी संसाधनों और भारतीय कलाकारों को जोड़कर ऐसा सिनेमाई संसार रचने की कोशिश की है, जिसे भारतीय दर्शकों के साथ विदेशी दर्शक भी देख सकें। फिल्म की शुरुआत रावण से होती है। यह चुनाव कथा का दृष्टिकोण बदल देता है। दर्शक पहले लंका के वैभव, रावण के व्यक्तित्व और उसके भीतर चलने वाले द्वंद्व से परिचित होते हैं। यश इस भूमिका में अपनी प्रभावशाली कद-काठी, संवाद अदायगी और पर्दे पर मौजूदगी से खास छाप छोड़ते हैं। रावण के क्रोध, अहंकार, शक्ति और उसके भीतर के असमंजस को उन्होंने प्रभावी ढंग से निभाया है। शरद केलकर की भारी आवाज इस चरित्र को अतिरिक्त प्रभाव देती है। जटायु के साथ संघर्ष और रावण से जुड़े कई दृश्य फिल्म के सबसे चर्चित हिस्सों में शामिल हैं।



राम की मर्यादा और रावण का प्रभाव

रणबीर कपूर के सामने राम की भूमिका मे सबसे बड़ी चुनौती संयम और गरिमा को पर्दे पर जीवंत करने की थी। 'एनिमल' के आक्रामक रणविजय से मर्यादित राम तक का उनका सफर अभिनय की अलग-अलग रंगत दिखाता है। वे राम को शांत, धैर्यवान और कर्तव्यनिष्ठ रूप मे प्रस्तुत करते हैं। हालांकि कुछ दृश्यों मे उनका संयम जरूरत से ज्यादा सपाट लगता है। चरित्र की आंतरिक शक्ति और क्षत्रिय तेज को कुछ और प्रभावशाली ढंग से उभारा जा सकता था। साई पल्लवी सीता के रूप मे सहजता और गरिमा लेकर आती हैं। उनके अभिनय मे बनावटीपन नही है और कुछ प्रसंगों मे वे चरित्र को मजबूती देती हैं। रवि दुबे लक्ष्मण के रूप मे ऊर्जा और भावनात्मक जुड़ाव पैदा करते हैं। अरुण गोविल दशरथ, लारा दत्ता कैकेयी, शोभना कैकसी और रकुल प्रीत सिंह शूर्पणखा के किरदारों मे दिखाई देते हैं। अनुपम खेर की आवाज जटायु के चरित्र को विशिष्ट पहचान देती है। फिल्म के अंत मे सनी देओल के हनुमान की झलक दूसरे भाग के लिए उत्सुकता बढ़ाती है। लेकिन यहां एक सवाल भी उठता है। कथा का भावनात्मक केंद्र राम होने के बावजूद कई दृश्यों मे रावण अधिक प्रभावशाली दिखाई देते हैं। यश का अभिनय इसकी एक वजह है, लेकिन पटकथा का झुकाव भी रावण के संसार की ओर अधिक महसूस होता है। राम और सीता के संबंधों, वनवास के निर्णय और परिवार के भीतर के भावनात्मक संघर्ष को जितना विस्तार मिलना चाहिए था, वह कई जगह नही मिल पाता।

तकनीक फिल्म की सबसे बड़ी ताकत

दृश्य प्रभावों के मामले मे 'रामायण' भारतीय सिनेमा के लिए एक बड़ी छलांग की तरह सामने आती है। डीएनईजी की तकनीकी टीम ने लंका, पुष्पक विमान, विशाल युद्ध दृश्यों, जटायु संघर्ष और पौराणिक संसार को बड़े पैमाने पर रचा है। इंद्र का ऐरावत, राक्षसों की कल्पनात्मक दुनिया और कुंभकर्ण जैसे प्रसंग दर्शकों को दृश्य वैभव का अनुभव कराते हैं। कई दृश्यों मे फिल्म का पैमाना हॉलीवुड की बड़ी फैंटेसी फिल्मों की याद दिलाता है। लेकिन हर दृश्य का भव्य होना अपने आप मे कहानी को प्रभावशाली नही बनाता। कहीं-कहीं दृश्य इतने अधिक डिजिटल और कृत्रिम लगते हैं कि कथा की स्वाभाविकता प्रभावित होती है। कुछ एनीमेटेड जीव और राक्षसी आकृतियां भी वास्तविकता का भ्रम पैदा करने के बजाय कंप्यूटर से निर्मित होने का अहसास कराती हैं। तकनीक का उद्देश्य दर्शक को कथा की दुनिया मे ले जाना होना चाहिए, न कि बार-बार उसे तकनीक की मौजूदगी का एहसास कराना। हंस जिमर और ए.आर. रहमान का संगीत भी फिल्म की बड़ी अपेक्षाओं का हिस्सा था। बैकग्राउंड स्कोर कई दृश्यों मे प्रभाव पैदा करता है, लेकिन कुछ समीक्षकों के मुताबिक संगीत कथा की भावनात्मक ऊंचाई के अनुरूप यादगार नही बन पाता। इतने बड़े महाकाव्य के लिए ऐसे गीत और धुनें अपेक्षित थीं, जो फिल्म खत्म होने के बाद भी दर्शकों के मन मे बनी रहें।

समीक्षाओं मे तारीफ भी, सवाल भी

फिल्म को लेकर समीक्षकों की राय एक जैसी नही है। 'द इंडियन एक्सप्रेस' की शुभ्रा गुप्ता ने इसके विशाल पैमाने, साहसिक दृश्यों और हंस जिमर-ए.आर. रहमान के संगीत की सराहना की, हालांकि उन्होंने कुछ हिस्सों मे सपाटपन की ओर भी संकेत किया। 'आउटलुक' की समीक्षा ने दृश्य वैभव और यश के रावण को प्रभावशाली माना, लेकिन कथा की भावनात्मक और दार्शनिक गहराई को अपर्याप्त बताया। 'मिंट' की समीक्षा मे भी फिल्म को बड़े पर्दे के लिए तैयार भव्य अनुभव तो माना गया, लेकिन इसे मजबूत नाटकीय कृति बनने मे पीछे बताया गया। इसके उलट, कुछ समीक्षकों ने इसे भारतीय सिनेमा के लिए तकनीकी और कल्पनात्मक उपलब्धि माना है। निर्देशक एस.एस. राजामौली ने इसके पैमाने, दृश्यों और कलाकारों के अभिनय की प्रशंसा की। लॉस एंजिल्स मे हुए प्रीमियर के बाद भी फिल्म के दृश्य प्रभावों और कलाकारों को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रियाएं सामने आईं। अंतरराष्ट्रीय दर्शकों के लिए अंग्रेजी संस्करण तैयार करने मे नई डबिंग तकनीक का इस्तेमाल भी चर्चा का विषय रहा।



आस्था और मनोरंजन के बीच संतुलन की चुनौती

'रामायण' के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल एक प्रसिद्ध कथा को दोबारा सुनाना नही, बल्कि उसकी मूल संवेदना को बनाए रखते हुए उसे नई पीढ़ी और वैश्विक दर्शकों तक पहुंचाना है। रामकथा मे वचनबद्धता, त्याग, मर्यादा, धैर्य, प्रेम और धर्मसंकट जैसे अनेक स्तर हैं। बड़े युद्ध, विशाल सेट और चमत्कारिक दृश्य इन मूल तत्वों का विकल्प नही हो सकते। फिल्म का पहला भाग कई बार इन भावनात्मक परतों की जगह दृश्य रोमांच को प्राथमिकता देता दिखाई देता है। करीब सवा तीन घंटे की अवधि के बावजूद कुछ प्रसंगों को जल्दबाजी मे निपटाया गया है, जबकि कुछ दृश्य जरूरत से ज्यादा विस्तार लेते हैं। वनवास के निर्णय, राम-सीता के संबंध और लक्ष्मण की प्रतिबद्धता जैसे प्रसंगों मे अधिक ठहराव होता तो दर्शक पात्रों से गहरा जुड़ाव महसूस कर सकते थे। दो भागों मे कथा बांटने का निर्णय फिल्म को विस्तार देने का अवसर देता है, लेकिन पहले भाग को अपने आप मे एक संपूर्ण भावनात्मक अनुभव बनाना भी जरूरी था। कुल मिलाकर 'रामायण: पार्ट वन' एक ऐसी फिल्म है जिसकी उपलब्धि और सीमाएं दोनों बड़ी हैं। यह तकनीक, बजट और दृश्य कल्पना के स्तर पर भारतीय सिनेमा की महत्वाकांक्षा का प्रदर्शन करती है। यश का रावण, जटायु प्रसंग, लंका का संसार और बड़े पर्दे पर रचे गए दृश्य इसकी प्रमुख ताकत हैं। दूसरी ओर, पटकथा की असमान गति, कुछ पात्रों का अधूरा विकास और भावनात्मक गहराई की कमी इसे एक महान सिनेमाई अनुभव बनने से रोकती है। फिल्म ने कमाई के मोर्चे पर अपनी ताकत दिखा दी है, लेकिन बॉक्स ऑफिस का रिकॉर्ड और कलात्मक उत्कृष्टता दो अलग कसौटियां हैं। 'रामायण' ने पहली कसौटी पर असाधारण सफलता हासिल की है। दूसरी कसौटी पर इसकी यात्रा अभी अधूरी है। दूसरे भाग से उम्मीद रहेगी कि वह पहले भाग की तकनीकी भव्यता को कथा की आत्मा, चरित्रों की गहराई और रामकथा के मूल भाव से जोड़ सके।



शनाया का सुनहरा अंदाज

एक्ट्रेस शनाया कपूर एक बार फिर अपने खूबसूरत अंदाज को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में उन्होंने सुनहरे रंग के चमकदार गाउन में अपनी कुछ बेहद खूबसूरत तस्वीरें साझा की हैं। तस्वीरों में उनकी खूबसूरती, मुस्कान और अदाओं का ऐसा संगम नजर आ रहा है कि फैन्स का नजरें हटाना मुश्किल हो रहा है। इन तस्वीरों में उनका शानदार परफ्यूम, प्यारी मुस्कान और दिलकश अंदाज देखने लायक है। सुनहरे गाउन के साथ हल्का पारदर्शी दुपट्टा उनके पूरे लुक को और भी खास बना रहा है। शनाया की इन तस्वीरों को देखकर उनके चाहने वाले भी उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं।



छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल

(श्रम विभाग)



श्री नरेन्द्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री

मंडल द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजना

श्री विष्णु देव साय माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना–

पात्रता – 18 से 60 आयु वर्ग के न्यूनतम् 90 दिवस पूर्व पंजीकृत निर्माण श्रमिक।

देय हितलाभ – सामान्य मृत्यु पर राशि रू. 1,00,000/– कार्य स्थल पर दुर्घटना से मृत्यु होने पर राशि रू. 5,00,000/– एवं कार्य स्थल पर दुर्घटना से दिव्यांगता होने पर राशि रू. 2,50,000/– एवं अपंजीकृत निर्माण श्रमिक की कार्य स्थल में दुर्घटना से मृत्यु होने पर 1,00,000/–(मृत्यु में सहायता राशि हितग्राही के उत्तराधिकारी को दिया जाता है)

मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना–

पात्रता – 59 से 60 आयु वर्ग के निर्माण श्रमिक जो विगत 03 वर्ष से मंडल में पंजीकृत हो।

देय हितलाभ – राशि रूपये 20,000/– एकमुश्त सहायता राशि।

मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना–

पात्रता – 60 वर्ष आयु पूर्ण कर चुके पंजीकृत निर्माण श्रमिक, जिनका मंडल में 10 वर्ष पूर्व का पंजीयन हो।

देय हितलाभ – प्रतिमाह रूपये 1500/– पेंशन जीवन पर्यन्त देय होगा। साथ ही पेंशनर की मृत्यु होने पर पेंशनर के आश्रित (पति/पत्नी) को पेंशन राशि का 50 प्रतिशत प्रतिमाह राशि रूपये 750/– पारिवारिक पेंशन के रूप में देय होगा।

मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना–

पात्रता – पंजीकृत ऐसे निर्माण श्रमिक जिनका निरंतर 03 वर्ष पूर्व का जीवित पंजीयन हो, छत्तीसगढ़ प्रदेश में किसी भी स्थान पर स्वयं अथवा परिवार के सदस्यों के नाम से आवास ना हो, पति व पत्नी दोनों के मंडल में पंजीकृत हितग्राही होने की स्थिति में योजना के तहत् केवल एक ही हितग्राही को लाभ देय होगा।

देय हितलाभ – पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को स्वयं के भूखंड पर आवास निर्माण/नवीन आवास क्रय के लिए राशि रूपये 1,50,000/– एकमुश्त अनुदान के रूप में।

मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना–

पात्रता – पंजीकृत निर्माण श्रमिक के प्रथम 02 बच्चें हेतु लाभ देय होगा।

देय हितलाभ – 1. कक्षा 10वीं एवं 12वीं से स्नातकोत्तर एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रम में 75 प्रतिशत एवं 75 प्रतिशत से अधिक अंक लाने पर राशि रू. 5,000 से 12,500 तक वार्षिक प्रोत्साहन राशि 2. छ0ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल के बोर्ड परीक्षा में प्रावीण्य सूची के प्रथम 10 में आने पर राशि रू. 1,00,000/– प्रोत्साहन राशि तथा दो पहिया वाहन क्रय किए जाने हेतु अनुदान राशि रू. 1,00,000/– 3. व्यवसायिक पाठ्यक्रम में अध्ययन हेतु समस्त शैक्षणिक शुल्क (शासकीय दर पर), छात्रावास में रहने व भोजन शुल्क तथा राशि रुपयें 2,000/–प्रतिवर्ष स्टेशनरी हेतु। 4. विदेश में अध्ययन हेतु वास्तविक व्यय अथवा अधिकतम राशि रू. 50,00,000/– सहायता राशि।

मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना–

पात्रता – मंडल में 03 वर्ष पूर्व पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के 02 अविवाहित पुत्रियों जिनकी आयु 18 वर्ष से 21 वर्ष हो एवं कम से कम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हो।

देय हितलाभ – राशि रू. 20,000/– एकमुश्त सहायता राशि।

मिनीमाता महतारी जतन योजना–

पात्रता –मंडल में बच्चें के जन्म के 01 वर्ष पूर्व पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक

देय हितलाभ – राशि रू. 20,000/– एकमुश्त सहायता राशि।

दीदी ई–रिक्शा सहायता योजना–

पात्रता – 18 से 50 आयु समूह के पंजीकृत निर्माण महिला श्रमिक, जो न्यूनतम 03 वर्ष से मंडल में पंजीकृत हो

देय हितलाभ – गुणवत्तायुक्त ई–रिक्शा लिए जाने के उद्देश्य से क्रयमूल्य राशि का 60% या अधिकतम राशि रू. 1,50,000/– जो भी कम हो, अनुदान दिया जावेगा।

निर्माण श्रमिक न हो हताश, ई-श्रम साथी ऐप में करे काम की तलाश।

डाउनलोड करे
eShram Sathi App

छत्तीसगढ़ संवाद RO No.: 14139/1

सम्मान से समृद्धि की ओर

छत्तीसगढ़

के अन्नदाता



प्रधानमंत्री किसान

सम्मान निधि

25 लाख+

किसानों को

प्रति वर्ष

₹6,000

की आर्थिक सहायता



/ChhattisgarhCMO

/DPRChhattisgarh

www.dprcg.gov.in

सुशासन से समृद्धि की ओर

छत्तीसगढ़ संवाद RO No.: 14168/ 260